RNI NO. DELHIN/2012/47450

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष 11, अंक 09
जुलाई 2024
मूल्य: ₹ 100/-

समाचार वार्ता

हर खबर पर नजर

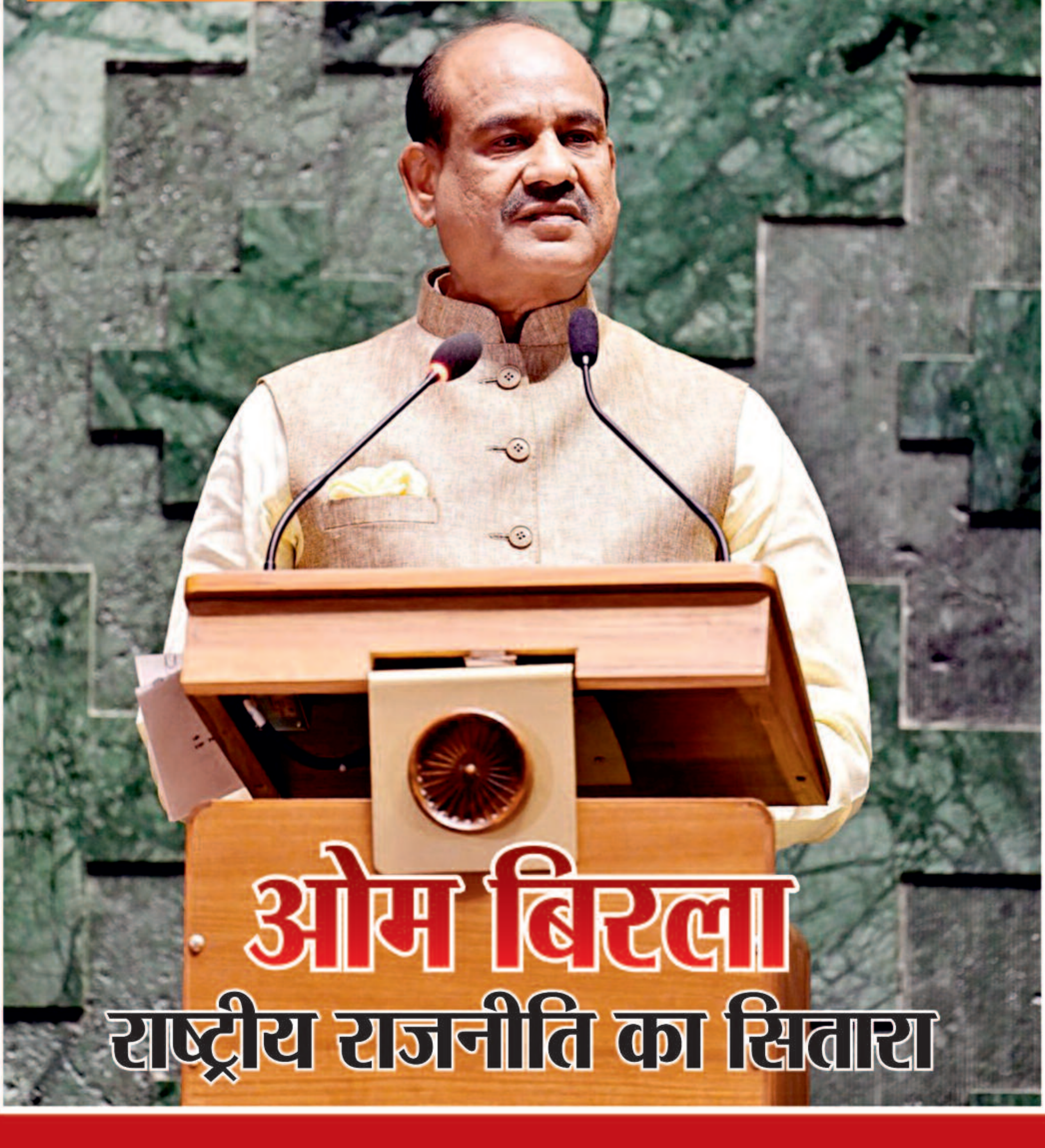

ओम बिरला

राष्ट्रीय राजनीति का सितारा

3n't3

RIIDHEE RAHMA

Parveen Aggarwal
(Proprietor)
+91 70655 53100
+91 99999 31100
riidhee_rahma@outlook.in

रिद्धि रामा
76/2, Budhpur, Alipur, Delhi-110036
Opp. Apna Ghar Aashram

समाचार वार्ता
हर खबर पर नजर

समाचार वार्ता

जुलाई 2024 // वर्ष : 11 // अंक : 09

संपादक : सुषमा राजीव
कार्यकारी संपादक : राजीव निशाना
उप संपादक : तरूण कुमार निमेष
विधि सलाहकार : रीतू रस्तोगी
विशेष संवाददाता : संजय शर्मा
बिजनेस हेड : अतुल कुमार
राज्य ब्यूरो इंचार्ज :
राजस्थान हेड : राजेश कुन्दरा
दिल्ली : रविन्द्र कुमार
हिमाचल प्रदेश : राजेश शर्मा
कानपुर : एम.ए.खान
डिजाइन : मीडिया हब

विशेष लेख

विशेष

07 ओम बिरला होने का मतलब सोने जैसे दिल..

राजस्थान के कोटा जिले में 23 नवंबर,1962 को जन्में ओम बिरला का समूचा राजनीतिक और सावर्जनिक जीवन सेवा, समर्पण और उससे उपजी सफलताओं से बना है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के रूप में काम प्रारंभ कर वे राजस्थान में युवा मोर्चा...

राष्ट्रीय

विशेष

08 18वीं लोकसभा का शुभारम्भ और...

संसद सत्र के पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहाँ एक ओर अपने तीसरे कार्यकाल पर देश की जनता को धन्यवाद देते हुए सर्वसहमति से चलाने के प्रयास के तहत पक्ष-विपक्ष से सहयोग की अपील तो की साथ ही आपात काल की 50वीं काली वर्षगांठ पर तत्कालीन...

राष्ट्रीय

विशेष

20 सरकार का 'अग्निपथ'

केंद्र सरकार ने 10 अलग-अलग मंत्रालयों के सचिवों को अग्निपथ योजना की समीक्षा का कार्य सौंपा है। सचिवों का यह समूह अग्निपथ योजना के जरिए सैनिकों की भर्ती को और अधिक आकर्षक बनाने के तरीके सुझाएगा। इस पहल के जरिए यदि अग्निपथ योजना में कोई कमी...

मार्केटिंग कार्यालय

एस 203, सिद्धार्थ पैलेस, चंदर नगर,
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
सम्पर्क सूत्र - +91-9654446699

Email : samacharvarta@gmail.com
editor@samacharvarta.com
www.samacharvarta.com

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक सुषमा राजीव द्वारा ग्राफिक प्रिंट, 383, एफआईई ग्राउंड फ्लोर, पटपडगंज इंडस्ट्रीयल एरिया दिल्ली द्वारा मुद्रित एवं 59-बी, जे-एक्सटेंशन लक्ष्मी नगर, दिल्ली-11092 से प्रकाशित। पत्रिका में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति हो अनिवार्य नहीं है। सभी विवादों का केन्द्र न्यायालय दिल्ली होगा।

RNI. No. : DELHIN/2012/47450

राष्ट्रीय

विशेष

26 राष्ट्रपति के अभिभाषण पर तीखे प्रहार और प्रतिकार

इस बार के सत्र में विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। उनकी आलोचनाओं का केंद्र बिंदु विभिन्न नीतिगत फैसलों और योजनाओं की प्रभावशीलता थी। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसकी नीतियां जनविरोधी हैं और वह केवल बड़े उद्योगपतियों के हित...

राष्ट्रीय

विशेष

28 60 करोड़ भारतीय कर रहे जल संकट

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार , पिछली शताब्दी में पानी का उपयोग जनसंख्या वृद्धि की दर से दोगुने से भी अधिक बढ़ गया है। 2025 तक, अनुमान है कि 1.8 बिलियन लोग पानी की कमी से ग्रस्त क्षेत्रों में रहेंगे, दुनिया की दो-तिहाई आबादी उपयोग, विकास और जलवायु...

संपादकीय

सुषमा राजीव
संपादक

आस्था के नाम पर तांडव कैसा?

हाथरस में एक सत्संग के दौरान हुए हादसे की न्यायिक जांच की घोषणा हो गई है और इस तरह अब इसके सहारे सरकार इस घटना पर उठने वाले सवालों के शांत होने की उम्मीद कर रही है। अब इस जांच के नतीजे कब आएंगे, किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, क्या कार्रवाई होगी, यह सरकार की इच्छाशक्ति पर निर्भर है। मगर इस घटना में जो हुआ, उसने न केवल किसी स्वयंभू बाबा और उसके समूह को, बल्कि सरकार और समूचे प्रशासन-तंत्र को कठघरे में खड़ा किया है। हालत यह है कि एक बाबा के कथित सत्संग के आयोजन को लेकर तो सभी स्तरों पर लापरवाही बरती ही गई, उससे उपजी अव्यवस्था की वजह से मची भगदड़ में कम से कम एक सौ इक्कीस लोगों के मारे जाने के बाद कार्रवाई के मामले में भी पुलिस और प्रशासन का जो रुख सामने आया है, वह हैरान करने वाला है।

भगदड़ के बाद छह सेवादार भाग गए थे, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया, मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर सहित 6 सेवादारों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा, पुलिस का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो 'भोले बाबा' से भी पूछताछ की जाएगी। हालांकि इसका कोई संतोषजनक जवाब सामने नहीं आया है कि बाबा का नाम पुलिस के पास दर्ज प्राथमिकी में क्यों नहीं है!

पहली जांच रिपार्ट के आधार पर सरकार ने 6 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। सवाल है कि आस्था के नाम पर सामने आई त्रासदी के लिए अगर सत्संग के आयोजकों की जिम्मेदारी बनती है, तो इस व्यापक लापरवाही में प्रशासन भी अपनी जवाबदेही से कैसे बच सकता है? अस्सी हजार लोगों की जुटान की इजाजत दे दी गई और ढाई लाख लोगों का जमावड़ा हो गया तो यह किसके आंख मूंद लेने की वजह से हुआ? इतनी बड़ी तादाद में लोगों के वहां आने के बाद प्रशासन ने क्या ऐसा किया ताकि आपात स्थितियों में बचाव हो सके?

जिस राज्य में आए दिन सरकार किसी भी कोने में छिपे अपराधियों को काबू में करने का दावा करती रहती है, उसमें पुलिस और खुफिया तंत्र के इतने बड़े जाल के बावजूद 'भोले बाबा' कैसे फरार हो गया? सब कुछ दुरुस्त होने के दावे के बीच एक बाबा भारी संख्या में लोगों को जुटा कर अपनी महिमा का बखान करता रहा। फिर भगदड़ के बाद उसके फरार हो जाने पर पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही और प्राथमिकी तक में उसका नाम नहीं है तो इसके पीछे क्या वजहें हैं?

सच यह है कि इस तरह बाबाओं के समाज या साधारण लोगों के बीच पांव पसारने और उन्हें मन-मुताबिक संचालित करने के लिए भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आम लोग अपनी जीवन-स्थितियों में बेहतरी और विकास लाने के साथ-साथ अच्छी पढ़ाई-लिखाई करें, नए विचारों से समृद्ध हों, इसकी व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है। मगर इसके समांतर संदिग्ध पृष्ठभूमि वाला कोई व्यक्ति बाबा का रूप धर कर लोगों को इस हद तक प्रभावित कर लेता है कि कुछ पीड़ित भी भगदड़ और लोगों के मारे जाने के लिए उस पर सवाल उठाने को गलत मानने लगते हैं।

आस्था के नाम पर इस तरह के सम्मोहन की स्थिति पैदा होने को लेकर क्या सरकारों की कोई जवाबदेही नहीं बनती? अव्यवस्था से उपजी कोई बेहद दुखद घटना हो जाती है, लोगों की जान चली जाती है, तब समूचा सरकारी तंत्र अत्यधिक सक्रिय दिखने लगता है। अफसोस की बात यह है कि जब ऐसी भयावह घटनाओं की भूमिका बन रही होती है, तब सरकार बेखबर रहती है। अगर समय रहते थोड़ी भी सक्रियता दिखाई जाती, तो शायद ऐसी त्रासदी से बचा जा सकता था!

असुविधा की सड़कों का टोल-टैक्स ज्यादती

● **ललित गर्ग**

बेहतर सेवाओं के नाम पर सरकारें कई तरह के शुल्क वसूलती है, इसमें कोई आपत्ति एवं अतिश्योक्ति नहीं है लेकिन सेवाएं बेहतर न हो फिर भी उनके नाम पर शुल्क या कर वसूलना आपत्तिजनक एवं गैर कानूनी है। यह एक तरह से आम जनता का शोषण है, धोखाधड़ी है। राजमार्ग एवं अन्य मार्गों पर बेहतर एवं सुविधाजनक सड़कों के नाम पर एजेंसियों द्वारा टोल टैक्स वसूला जाता है लेकिन विडम्बना एवं त्रासदी यह है कि टूटी-फूटी सड़कों के नाम पर भी टोल वसूला जाता है जो अन्यायपूर्ण एवं आपत्तिजनक है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के हालिया बयान में जनता के इस बड़े होते दुःख, धोखाधड़ी एवं शोषण पर न केवल दुःख जताया बल्कि ऐसी जबरन की जा रही वसूली को रोकने के लिये अधिकारियों को चेताया है।

अपनी बात को बेबाकी से कहने वाले नितिन गडकरी ने अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा कि यदि सड़कें अच्छी हालत में न हों और लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, तो राजमार्ग पर एजेंसियों द्वारा टोल टैक्स वसूलने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि टोल टैक्स वसूलने से पहले हमें अच्छी सेवाएं देनी चाहिए लेकिन हम अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिये टोल टैक्स वसूलने की जल्दी में रहते हैं। रोड टैक्स का उपयोग राज्य के भीतर सड़कों के रखरखाव और विकास के लिए किया जाना चाहिए न कि सरकार की आमद को बढ़ाने के लिये। ऐसे अनेक उदाहरण है कि बिना सुविधा एवं आवश्यकता के भी टोल टैक्स वसूला जा रहा है। राज्य सरकारें भी स्वतंत्र रूप से टोल वसूलती है। दूसरी ओर, टोल टैक्स एक उपयोगकर्ता शुल्क है जिसे वाहन मालिकों को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या निजी ठेकेदारों को कुछ टोल सड़कों, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, पुल और सुरंगों का उपयोग करने के लिए देना पड़ता है। अन्य सड़कों की तुलना में इन सड़कों को उच्च गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की माना जाता है। निश्चित रूप से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क-क्रांति की है बल्कि व्यवस्था की खामियों को सुधारने के भी सराहनीय प्रयास किये हैं।

किसी देश को विवेकपूर्ण, बेहतर सुविधाओं एवं विकास के नये मानकों के साथ चलाने के लिए सरकार को पात्र नागरिकों से बेहतर सुविधाओं के लिये कर एकत्र में कोई ऐतराज नहीं है; लेकिन सड़कें हो या अन्य सुविधाएं, अच्छी नहीं होने पर भी टोल टैक्स या अन्य टैक्स वसूलने पर उपभोक्ता स्वयं को ठगा हुआ एवं शोषित महसूस करता है जिसके कारण टोल टैक्स या अन्य टैक्स वसूलने वाली एजेंसियों के खिलाफ शिकायतें बढ़ती जा रही है। टोल टैक्स प्रणाली सरकार या निजी ठेकेदारों के लिए राजस्व सृजन का स्रोत नहीं होनी चाहिए, बल्कि जनता के लिए बेहतर और सुरक्षित सड़कें उपलब्ध कराने का साधन होनी चाहिए। निश्चित तौर पर गुणवत्ता की सेवा दिए बिना कोई टैक्स वसूलना उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी एवं अन्याय है।

यह बात हर सरकारी व निजी महकमे पर भी लागू होती है लेकिन यथार्थ में ऐसा होता नहीं है और बेहतर सेवा के बिना टैक्स वसूलने की स्थितियां लगातार बढ़ती जा रही है। इन स्थितियों को लेकर आम जनता एवं उपभोक्ताओं में विरोध एवं विद्रोह पनप रहा है, इसलिये सरकार एवं ऐसी एजेन्सियों के खिलाफ लोग लोक अदालतों से लेकर विभिन्न अदालतों के दरवाजे खटखटाते रहते हैं। किसी भी विभाग को अपनी खामियों पर पर्दा डालने के बजाय सेवा में सुधार की पहल करनी चाहिए। अब चाहे मामला राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्यरत एजेंसियों का हो या फिर बिजली-पानी जैसे मूलभूत जरूरतों वाले विभागों का, अधिकारियों को उपभोक्ताओं के प्रति संवेदनशील एवं जिम्मेदार होना चाहिए।

राजमार्गों पर यात्रा करने के दौरान आपके बैंक खाते या डिजिटल वॉलेट से पैसा कट जाता है। इसमें भी गलत तरीके से पैसे कटने की शिकायतें बढ़ती जा रही है। किसी व्यक्ति के फास्टैग से बिना टोल से गुजरे टोल टैक्स काट लिया जाता है या ज्यादा टोल वसूल लिया जाता है, जो उपभोक्ताओं के लिये परेशानी का सबब है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार, सड़क निर्माण और रखरखाव के अपने लक्ष्यों को हासिल करने में विफल रहा है। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि एचएचआई ने टोल अनुबंधों को आकार देने और निगरानी के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है और टोल सड़कों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की है। रिपोर्ट में टोल संग्रह प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी और दोषपूर्ण टोल प्लाजा, ओवरचार्जिंग और लंबी कतारों के कारण सड़क उपयोगकताओं को होने वाली परेशानी और असुविधा पर भी प्रकाश डाला गया है। इन सभी हालातों को देखते हुए भारत में राजमार्गों एवं सुविधा की सड़कों के नाम पर हो रही टोल टैक्स वसूली को औचित्यपूर्ण एवं न्यायसंगत बनाने की अपेक्षा है। सुविधा के नाम असुविधाओं, असुरक्षा एवं धोखाधड़ी की बढ़ती स्थितियों को गंभीरता से लेना होगा।

ओम बिरला

कैसे बना राष्ट्रीय राजनीति का सितारा

प्रो. संजय द्विवदी

ओम बिरला में ऐसा क्या है जो उन्हें लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी पर पहुंचाता है। अपने कोटा शहर में जरूरतमंद लोगों को कपड़े, दवाएं, भोजन पहुंचाते-पहुंचाते बिरला कब राष्ट्रीय राजनीति के सितारे बन गए, यह एक अद्भुत कहानी है। प्रधानमंत्री ने सदन में उनके द्वारा चलाए जा रहे अनेक सामाजिक कार्यों की चर्चा की। उनकी सरलता,सहजता और सदन चलाने की उनकी क्षमताएं प्रमाणित हैं। अब जब वे ध्वनिमत से लोकसभा के अध्यक्ष चुने जा चुके हैं, तब उन पर

ओम बिरला होने का मतलब सोने जैसे दिल वाला सामाजिक कार्यकर्ता

बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। यह भी शुभ रहा कि कांग्रेस ने प्रारंभिक चचाओं के बाद भी मत विभाजन की मांग नहीं की और उनका चयन सर्वसम्मत से हुआ। इससे संसद की गरिमा बनी और परंपराओं का पालन हुआ है। उम्मीद की जानी चाहिए आने वाले समय में लोकसभा ज्यादा बेहतर

तरीके से अपने कामों को अंजाम दे सकेगी।

श्री बलराम जाखड़ के बाद वे दूसरे ऐसे सांसद हैं, जिन्होंने यह गरिमामय पद दुबारा संभाला है। इस बात को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि नए सांसदों को बिरला से सीखना चाहिए। मोदी ने कहा कि ह्वसंसद 140 करोड़ देशवासियों की आशा का केंद्र है। सदन में आचरण और नियमों का पालन जरूरी है। सदन की गरिमा और परंपराओं का पालन अध्यक्ष की बहुत महती जिम्मेदारी है ह्व उम्मीद की जानी चाहिए कि संसद में लोकसभा अध्यक्ष के रूप में बिरला जी का यह कार्यकाल उदाहरण बनेगा। जहां गंभीर बहसें होंगी और शासकीय काम के साथ विमर्शों का नया आकाश खुलेगा।

राजस्थान के कोटा जिले में 23 नवंबर,1962 को जन्में ओम बिरला का समूचा राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन सेवा, समर्पण और उससे उपजी सफलताओं से बना है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के रूप में काम प्रारंभ कर वे राजस्थान में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे 2003, 2008 और 2013 में तीन बार राजस्थान विधानसभा में विधायक निर्वाचित किए गए। 2014 से वे लगातार तीसरी बार लोकसभा पहुंचे हैं। इस तरह वे एक सफल जनप्रतिनिधि के रूप में कोटा के लोगों का दिल जीतते रहे हैं। 17 वीं लोकसभा में अध्यक्ष चुने जाते ही वे राष्ट्रीय फलक पर छा गए। अपने तमाम फैसलों की तरह उस समय नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक विश्वेषकों को चौंकाते हुए बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा था। किंतु अपनी सौजन्यता, कुशल सदन संचालन और लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव न होने के बाद भी अकेले वरिष्ठ सांसदों के पैनल के आधार उन्होंने सदन चलाया । उनका सहज अंदाज और हल्की मुस्कान,मीठी डांट से सदन को चलाने का तरीका उन्हें इस बार इस पद का स्वाभाविक उत्तराधिकारी बना चुका था। अब कोटा की स्थानीय राजनीति से राष्ट्रीय फलक पर आए बिरला सदन की उपलब्धि बन चुके हैं।

बिरला राजनीति में आने से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े थे। उनके मन में समाजसेवा की भावना इसी संगठन से उपजी और वे विविध प्रकल्पों के माध्यम से इसी काम में रम गए। उन्होंने अपने क्षेत्र में 2012 में परिधान नाम कल्याणकारी कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसके तहत समाज के कमजोर वर्गों को किताबें और कपड़े वितरित किए जाते थे। इसके साथ ही रक्तदान और मुफ्त दवा वितरण के आयोजनों से वे लोगों के दिलों में उतरते चले गए। फिर उन्होंने मुफ्त भोजन कार्यक्रम भी चलाया। उनका संकल्प था उनके लोग भूखे न सोएं। इस तरह वे बहुत संवेदनशील और बड़े दिलवाले सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता की तरह सामने आते हैं। यह उन हाशिए के लोगों की दुआएं ही थीं कि बिरला आज सत्ता राजनीति के शिखर पर हैं। भाजपा को एक दल के रूप में इस बार लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं है और उसकी निर्भरता राजग के सहयोगियों पर बढ़ी है। इसी तरह सदन में प्रतिपक्ष ज्यादा ताकतवर हुआ है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी मौजूद होंगे। मोदी की तीसरी सरकार में नेता प्रतिपक्ष का पद मिलना भी एक बड़ी सूचना है। पिछले दो सदनों में कांग्रेस के इतने सदस्य नहीं थे कि वह नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल कर सके। इससे नेता प्रतिपक्ष अब लोकलेखा समिति के अध्यक्ष भी होंगे और सरकारी खर्चों पर टिप्पणी कर सकेंगें। इस बदले हुए परिदृश्य में सदन में प्रतिपक्ष की आवाज भी प्रखर होगी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव देते हुए सत्ता पक्ष पर अंकुश और प्रतिपक्ष को संरक्षण देने की अपील की। उम्मीद की जानी कि ओम बिरला अपने बड़े दिल से सदन की गरिमा को नई ऊंचाई प्रदान करेंगें। फिलहाल तो उन्हें शुभकामनाएं ही दी जा सकती हैं।

(लेखक भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली के पूर्व महानिदेशक हैं।)

18वीं लोकसभा का शुभारम्भ और आपातकाल की काली 50वीं वर्षगांठ

संसद सत्र के पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहाँ एक ओर अपने तीसरे कार्यकाल पर देश की जनता को धन्यवाद देते हुए सर्वसहमति से चलाने के प्रयास के तहत पक्ष-विपक्ष से सहयोग की अपील तो की साथ ही आपात काल की 50वीं काली वर्षगांठ पर तत्कालीन कॉंग्रेस सरकार और प्रधानमंत्री श्रीमती गाांधी की तानाशाही पूर्ण रवैये और देश को जेल मे परिवर्तित कर विपक्षी सदस्यों को जेलों मे डालने पर प्रकाश...

● **राजीव कुमार**

इसे विश्व के सबसे बड़े लोकतन्त्र के मंदिर की 18वीं लोकसभा का सत्रारंभ का सुखद संयोग कहें या दुःखद दुर्योग कि एक ही दिन देश मे लोकतन्त्र के नाम कॉंग्रेस शासित तानाशाह प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा देश मे थोपी गयी स्याह काली आपातकाल की 50वी वर्षगांठ और 18वीं लोकसभा का सत्र आरंभ ऐसे समय हो रहा हैं जब संसद के दोनों पक्ष के लोग लोकतन्त्र की रक्षा करने की दुहाई देकर एक दूसरे पर संविधान मे बदलाव का आरोप लगा रहे हैं। दोनों पक्षो के तेवर देख अनुमान लगाना कठिन न होगा कि आने वाले संसद के सत्र का स्वरूप कैसा होने वाला हैं। संसद सत्र के पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहाँ एक ओर अपने तीसरे कार्यकाल पर देश की जनता को धन्यवाद देते हुए सर्वसहमति से चलाने के प्रयास के तहत पक्ष-विपक्ष से सहयोग की अपील तो की साथ ही आपात काल की 50वीं काली वर्षगांठ पर तत्कालीन कॉंग्रेस सरकार और प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी की तानाशाही पूर्ण रवैये और देश को जेल मे परिवर्तित कर विपक्षी सदस्यों को जेलों मे डालने पर प्रकाश डाला और देश को आगाह किया कि हमे ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना होगा ताकि कोई भी तानाशाह संविधान की हत्या कर लोकतन्त्र का बलात हरण कर स्थगित करने की हिमाकत न कर सके।

वहीं दूसरी ओर इंडि गठबंधन के लोगो द्वारा हाथों मे संविधान की प्रतियों के साथ संविधान की रक्षा की प्रतिवद्धता जतलाना आश्चर्य चकित करने वाला था। जो कॉंग्रेस संविधान की रक्षा करने की कसमें खा रही थी, उसी कॉंग्रेस ने आज ही के दिन 25 जून 1975 को देश मे आपातकाल लगा कर देश के संविधान को समाप्त कर स्थगित कर दिया था। इसी आपातकाल मे इंडि गठबंधन के घटक दलों के जिन नेताओं को बिना किसी कारण के 19 माह तक गिरफ्तार कर तत्कालीन कॉंग्रेस सरकार ने बिना किसी प्रमाण और कारणों के जेलों मे डाल दिया था, वे ही घटक दल और उनके नेता संविधान की रक्षा के नाम पर कॉंग्रेस के साथ खड़े हैं। ये लोकतन्त्र की बड़ी भरी विडम्बना थी और देश का दुर्भाग्य था कि जिस कॉंग्रेस सरकार पर देश के संविधान की रक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, उसी कॉंग्रेस ने संविधान की हत्या कर देशभर के विपक्षी दलों के नेताओं को जेल मे डाल दिया।

अभिव्यक्ति की आजादी तो सपना हो गया था। मीडिया और प्रेस पर सेंसरशिप लगा कर समाचार पत्रों की आजादी समाप्त कर दी गयी थी।

इसी बीच इंडि गठबंधन ने सर्वसम्मति से राहुल गांधी को विपक्षी दलों का नेता चुन लिया। यूं तो राहुल गांधी हमेशा बड़ी जिम्मेदारियाँ लेने से बचते रहे क्योंकि इतने लंबे राजनैतिक कैरियर के बावजूद भी उनमे वो राजनैतिक परिपक्वता नजर नहीं आती जो इतने अनुभव के बाद किसी सयाने और प्रौढ़ राजनेता से की जानी चाहिये। आशा ही नहीं विश्वास हैं कि राहुल गांधी विपक्षी दल के नेता के रूप मे अपने आप को स्थापित कर एक नया उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।

संसद मे प्रोटेम स्पीकर के रूप मे श्री भरतृहरि महताव के चुनाव जैसे साधारण मुद्दे को असाधारण बना कर कॉंग्रेस ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया और सत्ताधारी दल का लोकसभा अध्यक्ष की चली आ रही निर्विरोध चुनने की प्रथा मे रोढ़ा अटकाकर अबरोध पैदा करने के प्रयास किया। कॉंग्रेस की मांग थी कि सत्ताधारी एनडीए इस बात का आश्वासन दे कि लोकसभा का उपाध्यक्ष विपक्ष का हो? सत्तापक्ष के लोगो द्वारा इस तरह की किसी भी पूर्व शर्त स्वीकार नहीं किया जाने से कॉंग्रेस द्वारा के सुरेश को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। जब उपसभापति का चुनाव होगा तब इस विषय मे खुले दिल से विचार किया जाएगा। इस तरह के अविश्वास के कारण ही संसद मे 26 जून 2024 को सभापति पद के लिये एनडीए के प्रत्याशी के रूप मे श्री ओम बिड़ला और इंडि गठबंधन के प्रत्याशी के रूप मे श्री के॰ सुरेश के बीच हुए चुनाव के रूप मे अंततः ध्वनि मत से विजयी घोषित किए गए। ये जानते हुए भी कि इंडि गठबंधन के पक्ष मे आवश्यक संख्या बल नहीं है, कॉंग्रेस ने मतविभाजन की मांग न कर अपनी जग हँसाई भी करवाई। यदि राहुल गांधी के पहले संवैधानिक पद विपक्षी दल के नेता के रूप मे स्पीकर के पद की चुनावी रणनीति को उनकी पहली परीक्षा माने तो राहुल गांधी इस परीक्षा मे असफल माने जाएंगे।

सभापति के चुनाव के बाद माननीय सांसद महोदयों द्वारा स्पीकर महोदय श्री ओम बिड़ला को दिये गए संदेशों की औपचारिकताओं के बीच कुछ सदस्यों द्वारा उनको प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से नसीहते भी दी। सपा के अखिलेश यादव ने ओम बिड़ला जी द्वारा पिछले कार्यकाल मे 150 संसद सदस्यों को निलंबित किये जाने की घटना को दुबारा न करने की सलाह दी। कदाचित अखिलेश यादव, माननीय संसद सदस्यों को भी संसद की तय मान्यताओं और नियमों के अनुरूप आचरण करने का भी संदेश देते, जिसके के कारण पिछले कार्यकाल मे संसद सदस्यों की बर्खास्तगी जैसी अप्रिय कदम उठाने के लिये सभापति को बाध्य होना पड़ा। लेकिन आज के सत्र के दौरान ही, सख्त अनुशासन पसंद सभापति ओम बिड़ला जी द्वारा एक सदस्य के लगातार बोलने पर आसंदी से खड़े हो कर उन्हे बैठने के लिये कहते हुए सदन के सारे सदस्यों को ये संदेश दिया कि जब सभापति आसंदी से खड़े होकर बोले तो सारे सदस्यों को बैठ जाना चाहिये। चूंकि सदन के ये पहला दिन था और बहुत से सदस्य नये हैं, पर आगे पाँच साल इस बात का ध्यान रक्खा जाना चाहिये। ये संदेश इस बात की तरफ साफ इशारा था कि सभापति द्वारा संसद की कार्यवाही तय नियमों और अनुशासन के साथ ही चलाई जायेगी।

संसद की कार्यवाही के अंत मे सभापति श्री ओम बिड़ला द्वारा 25 अगस्त 1975 को तत्कालीन कॉंग्रेस सरकार की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा 50 वर्ष पूर्व देश मे लागू किये गये आपातकाल पर, निंदा प्रस्ताव पढ़ना आश्चर्य और अभूतपूर्व था।

उन्होने प्रधानमंत्री और कॉंग्रेस की निंदा और आलोचना करते हुए उन्हे तानाशाह बताते हुए लाखों विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, प्रेस पर पाबंदी, न्यायपालिका पर अंकुश और देश के आम नागरिकों के लोकतान्त्रिक अधिकारों की समाप्ति की कड़ी निंदा की और आपातकाल को देश के लोकतन्त्र के लिये कलंक और काला अध्याय बताना चौंकने वाला अभूतपूर्व साहसिक कदम था। संसद मे राहुल गांधी द्वारा जेब मे संविधान की प्रति रख कर अपने आप को संविधान की रक्षा का पुरोधा बताने पर उन्हे उनकी दादी श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा, संविधान पर किये गए कुठराघात पर आईना दिखा दिया। स्वाभाविक था कॉंग्रेस के सदस्यों ने संसद मे नारेबाजी कर इस निंदा प्रस्ताव का विरोध किया लेकिन सपा, टीएमसी और अन्य दलों द्वारा आपातकाल के इस निंदा प्रस्ताव के कॉंग्रेसी का साथ न मिलना बताता हैं कि कॉंग्रेस के उस तानाशाही पूर्ण आपातकाल को देश आज भी भूला नहीं हैं। भारत के मजबूत लोकतन्त्र मे तानाशाही लाने और संविधान को बदलने का दुस्साहस करने वालों को उसी तरह मुँह की खानी पड़ेगी जैसे कि आज से 50 वर्ष पूर्व आपातकाल लागू करने पर श्रीमती इन्दिरा गांधी और कॉंग्रेस को खानी पड़ी थी।

राहुल के आरोपों का पीएम मोदी ने दिया जवाब

राहुल गांधी के भाषण ने जहां कांग्रेस के समर्थकों में नई ऊर्जा का संचार किया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2 घंटे से लंबे मैराथन भाषण में बीजेपी और एनडीए सरकार का पक्ष मजबूती से देश के सामने रखने की कोशिश की।

● शिवानी नारायण

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा किए गए तीखे हमलों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। राहुल गांधी के द्वारा शिव की तस्वीर दिखाने, अग्निवीर को वापस लेने का वादा करने, संविधान पर हमले का आरोप लगाने और बीजेपी के नेताओं को यह कहना कि 'आप हिंदू नहीं हो' इन तमाम बातों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। हालांकि, मणिपुर के मसले पर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा।

राहुल गांधी के भाषण ने जहां कांग्रेस के समर्थकों में नई ऊर्जा का संचार किया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2 घंटे से लंबे मैराथन भाषण में बीजेपी और एनडीए सरकार का पक्ष मजबूती से देश के सामने रखने की कोशिश की।

राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि बीजेपी के लोग अपने आप को हिंदू बताते हैं लेकिन नफरत और हिंसा की बात करते हैं। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है यह कहा जा रहा है कि हिंदू हिंसक होते हैं। मोदी ने कहा कि यह देश शताब्दियों तक इस बात को नहीं भूलेगा।

मोदी ने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ने की कोशिश की थी। इनके साथी हिंदू धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया जैसे शब्दों से करें, यह देश इसे कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सदन में कल का दृश्य देखकर अब हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा कि क्या यह अपमानजनक बयान कोई संयोग है या बड़े प्रयोग की तैयारी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब देने के लिए स्वामी विवेकानंद के 131 साल पहले शिकागो में दिए गए बयान का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से आता हूं जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और वैश्विक स्वीकृति सिखाई है।

चुनाव नतीजों पर भी दिया जवाब

चुनाव नतीजे के बाद बार-बार कांग्रेस और राहुल गांधी ने कहा है कि यह जनादेश पूरी तरह मोदी सरकार के खिलाफ है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की नैतिक हार है। मोदी ने इसका भी जवाब दिया और कहा कि 16 राज्यों में कांग्रेस जहां अकेली लड़ी है, वहां उसका वोट शेयर गिर चुका है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने सहयोगियों के जो वोट खाए हैं, अगर वह न खाए होते तो लोकसभा में उसके लिए इतनी सीटें जीत पाना भी बेहद मुश्किल था। मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम देश के लोगों के मन में यह बात बैठाने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने हमें हरा दिया है और ऐसा कहकर वह छोटे बच्चे का मन बहलाने की कोशिश कर रही है।

राहुल गांधी ने अपने भाषणों में कई बार कहा है कि सेना को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इसका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में हमारी सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं थी।

अग्निवीर पर झूठ फैला रही कांग्रेस: मोदी

राहुल गांधी ने अपने भाषण में अग्निवीर योजना का मुद्दा उठाया था और एक बार फिर कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में आएगी तो अग्नि वीर योजना को बंद कर दिया जाएगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अग्निवीर योजना आर्मी की नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना है। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेना में भर्ती को लेकर कांग्रेस की ओर से सरासर झूठ फैलाया जा रहा है ताकि देश के नौजवान सेना में न जाएं।

उन्होंने कहा कि आखिर किसके लिए कांग्रेस हमारी सेना को कमजोर करना चाहती है और किसके फायदे के लिए कांग्रेस वाले सेना के संबंध में इतना झूठ फैला रहे हैं?

मणिपुर मई, 2023 से जातीय हिंसा की आग में जल रहा है। कांग्रेस और विपक्षी दल लगातार मणिपुर को लेकर मोदी सरकार को घेर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पर बयान देने की मांग कर चुके हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषण में मणिपुर का मुद्दा उठाया था। यह माना जा रहा था कि मोदी इस मुद्दे पर कुछ बोलेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

400 पार के आंकड़े से बहुत दूर रह गया एनडीए

2024 में लोकसभा चुनाव का मुकाबला निश्चित रूप से बेहद जोरदार था। इसमें एनडीए के चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो उनके सामने इंडिया गठबंधन था। चुनाव के नतीजे बीजेपी की उम्मीदों के मन मुताबिक नहीं आए क्योंकि उसने एनडीए के लिए 400 पार का टारगेट तय किया था जबकि एनडीए को 292 सीटें ही मिली।

भाजपा अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा भी हासिल नहीं कर सकी। दूसरी ओर कांग्रेस ने अपनी सीटों का आंकड़ा 2019 के मुकाबले लगभग दो गुना कर लिया।

आगे भी देखने को मिल सकती है जुबानी जंग

राहुल गांधी ने बतौर नेता प्रतिपक्ष अपने पहले भाषण से इस बात का संदेश देने की पूरी कोशिश की कि अगले 5 साल सदन में मोदी सरकार के लिए आसान नहीं रहेंगे। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में ही जिस तरह राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का आमना-सामना हुआ है, उससे साफ है कि संसद के सभी सत्रों में इन दोनों नेताओं में जोरदार जुबानी जंग देखने को मिल सकती है।

कांग्रेस के तीन पूर्व पीएम थे आरक्षण के विरोधी: मोदी

लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही थी कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार संविधान और आरक्षण पर हमला कर रहे हैं। मोदी ने अपने भाषण में इसका जवाब दिया और कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने हमेशा आरक्षण का विरोध किया था।

उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया और अपनी पार्टी के दलित नेता बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। उन्होंने आपातकाल का भी जिक्र किया।

1 जुलाई, 2024 को बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपना पहला भाषण दिया था। उनकी कई बातों पर सत्ता पक्ष ने घोर आपत्ति जताई थी और तीखा विरोध किया था।

नेता विपक्ष के रूप में राहुल ने बीजेपी को खूब छकाया

● **कमलेश कुमार सिंह**

नेता प्रतिपक्ष के रुप मे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने पहले ही भाषण में न केवल अपने आपको स्थापित किया ,बल्कि भाजपा की दुखती रग को कई बार छेड़ने में कामयाब हुए। लोकसभा में राहुल गांधी का अलग ही रूप दिखा। नेता विपक्ष के रूप में अपने पहले ही भाषण में वो न केवल बीजेपी पर हमलावर थे बल्कि अपनी बातों को तर्कसंगत तरीके से रख भी रहे थे। पिछले 10 सालों में पहली बार लोकसभा में बीजेपी बैकफुट पर दिखी। 2014 के बाद शायद पहली बार लोकसभा में ऐसा मंजर था कि राहुल गांधी के स्पीच के सामने बीजेपी असहाय दिख रही थी. राहुल को रोकने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी 2 बार उठे, राजनाथ सिंह भी 2 बार उठे, गृहमंत्री अमित शाह कम से कम 4 बार, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी एक बार उठे। लेकिन राहुल बीजेपी को लगातार घेरते रहे। हालॉकि कई बार राहुल गांधी सदन को गुमराह करते रहे। लेकिन भारतीय राजनीति में सदन में गुमराह करने का फैशन अब पुराना हो गया है...

लोकसभा स्पीकर को भी लिया आड़े हाथों

राहुल ने स्पीकर ओम बिरला को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा जब स्पीकर मुझसे हाथ मिलाते समय सीधे रहते हैं, मोदीजी से हाथ

राहुल सीख रहे हैं कटाक्ष करने का गुर

भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद भाषण कला में कटाक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है. कटाक्ष सुनने में जनता को भी मजा आता है. अभी तक राहुल गांधी का भाषण सीधा और सपाट होता था. इस कला में प्रधानमंत्री भारी पड़ते रहे है। इस कला का परिचय राहुल गांधी ने भी खूब दिया। राहुल ने पहले कहा कि प्रधानमंत्री ने बोला है मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान से. ये मैंने नहीं पीएम मोदी ने बोला है। राहुल ने कहा,कि मैं पीएम की इज्जत कर रहा हूं। लेकिन पीएम ने खुद कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं. पीएम ने कहा है. पीएम मोदी को डायरेक्ट ऊपर से मैसेज आया और उन्होंने नोटबंदी कर दी। अरबपतियों की मदद के लिए जीएसटी और नोटबंदी की गई।

दूसरे वाक्या में राहुल गांधी ने कहा कि इनकम टैक्स, ईडी सब स्मॉल बिजनेस ऑनर्स के पीछे पड़े रहते हैं जिससे अरबपतियों का रास्ता साफ हो. मैं गुजरात गया था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालों ने बताया कि अरबपतियों का रास्ता साफ करने के लिए जीएसटी लाया गया. इस पर किसी ने कहा कि गुजरात भी जाते हैं क्या. राहुल गांधी ने कहा कि जाता रहता हूं. उन्होंने ये भी कहा कि इस बार गुजरात में आपको हराएंगे. लिख के ले लो आपको इस बार गुजरात में हराएंगे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदीजी अयोध्या के लोगों की छोड़ो, बीजेपी वालों को डराते हैं।

मोदी- शाह-राजनाथ का बार-बार खड़ा होना भी काम नहीं आया

राहुल लोकसभा में बीजेपी पर हमलावर थे और बीजेपी लगातार उन्हें घेरने का प्रयास कर रही थी. पर सफल नहीं हो पा रही थी. राहुल ने मोदीजी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने कभी किसी पर हमला नहीं किया. इसका कारण है. हिंदुस्तान अहिंसा का देश है, यह डरता नहीं है. हमारे महापुरुषों ने यह संदेश दिया- डरो मत, डराओ मत. शिवजी कहते हैं- डरो मत, डराओ मत और त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं. दूसरी तरफ जो लोग अपने आपको हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा-हिंसा-हिंसा, नफरत-नफरत-नफरत. आप हिंदू हो ही नहीं. हिंदू धर्म में साफ लिखा है सच का साथ देना चाहिए।राहुल गांधी के इस बयान पर एक समय ऐसा लगा कि बीजेपी इसे ट्रैप कर लेगी. सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया. पीएम मोदी खुदअपनी चेयर पर उठकर खड़े हुए और इसे गंभीर बात बताया. पीएम मोदी ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात है. इसके बावजूद हिंदू वाली बात मुद्दा नहीं बन पाया. अग्निवीर , एमएसपी आदि के मुद्दे पर बोलते हुए राहुल गांधी को बीजेपी ने ट्रैप करने की कोशिश की पर सफल नहीं हो सकी।

मिलाते समय झुकते हैं। गांधी ने कहा कि आप सदन के कस्टोडियन हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है. आपको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए. मैं आपके सामने झुकूंगा, पूरा विपक्ष आपके सामने झुकेगा. लोकसभा में स्पीकर से बड़ा कोई नहीं होता, स्पीकर का बयान ही आखिरी होता है.

सच झूठ से बेपरवाह

लोकसभा चुनावों में संविधान बचाओ नारे को मिले समर्थन के बाद से कांग्रेस को ये अहसास हो गया है कि झूठ या सही बस नरेटिव गढ़ने से ही विजय संभव है. शायद यही कारण है कि कॉन्फिडेंस के साथ नरेटिव सेट करने पर ही जो दिया जा रहा है. राहुल गांधी ने अग्निवीर के संबंध में जो भी कुछ बोला उसे तथ्यहीन ही कहा जा सकता है.किसानों के बारे में भी बोलते हुए उन्होंने कुछ बातें ऐसी कीं जिन्हें तथ्यात्मक रूप से गलत कहा जा सकता है.लेकिन राहुल गांधी जिस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रख रहे थे मायने वही रखता है. नेता का काम ही होता है कि वो सच या झूठ जो भी बोलो जनता उसे सही माने. इसलिए सही मायने में देखा जाए तो राहुल गांधी का भारतीय नेता वाला अवतार अब हो चुका है. गृहमंत्री अमित शाह ने शायद इसी लिए ही स्पीकर ओम बिरला से अपील की है कि तथ्यहीन बातों की जांच की जाए.

राहुल गांधी स्पीच में शुरू से हमलावर रहें .

बीजेपी जब तक एक हमले का जवाब तैयार करती तब तक राहुल दूसरा फायर कर देते. संविधान के साथ सत्ता पक्ष के व्यवहार पर हमला करते हुए उन्होंने सबसे पहले बीजेपी पर देश की जनता को डराने का आरोप लगाया. सभी धर्मों का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सभी धर्म प्रेम करना सिखाते हैं . इसी संदर्भ में उन्होंने बीजेपी की कमजोर नस अयोध्या की हार पर बोलना शुरू किया. राहुल गांधी ने कहा कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या ने बीजेपी को मैसेज दिया. अवधेश पासी की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि ये मैसेज आपके सामने बैठे हुए हैं. मैंने कल कॉफी पीते हुए इनसे पूछा कि हुआ क्या. आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो. इन्होंने कहा कि पहले दिन से पता था. अयोध्या में एयरपोर्ट बना, जमीन छिनी गई और आज तक मुआवजा नहीं मिला है. अयोध्या के उद्घाटन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ. अंबानी जी थे, अडानी जी थे, लेकिन अयोध्या का कोई नहीं था।

अभी अयोध्या की बात चल ही रही थी कि राहुल गांधी ने अग्निवीर मुद्दे को टार्गेट कर दिया. एक अग्निवीर की शहादत का जिक्र करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते. उसके परिजनों को पेंशन नहीं मिलेगी. आम जवान को पेंशन मिलेगी, सरकार उसकी मदद करेगी लेकिन अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता. अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है. राहुल गांधी ने कहा कि आप जवान और जवान के बीच में फूट डालते हो और फिर अपने आपको देशभक्त कहते हो. कुल मिलाकर राहूल गाँधी ने लगभग दो घंटे तक भाजपा को हर मुद्दे पर खुब फसाया, भाजपा पहली बार बेचारा और बेवश दिखी । अगर ऐसी ही राहुल स्कोर करते रहे , तो जल्दी ही पप्पू बाला टैग से निकल जाएंगे।

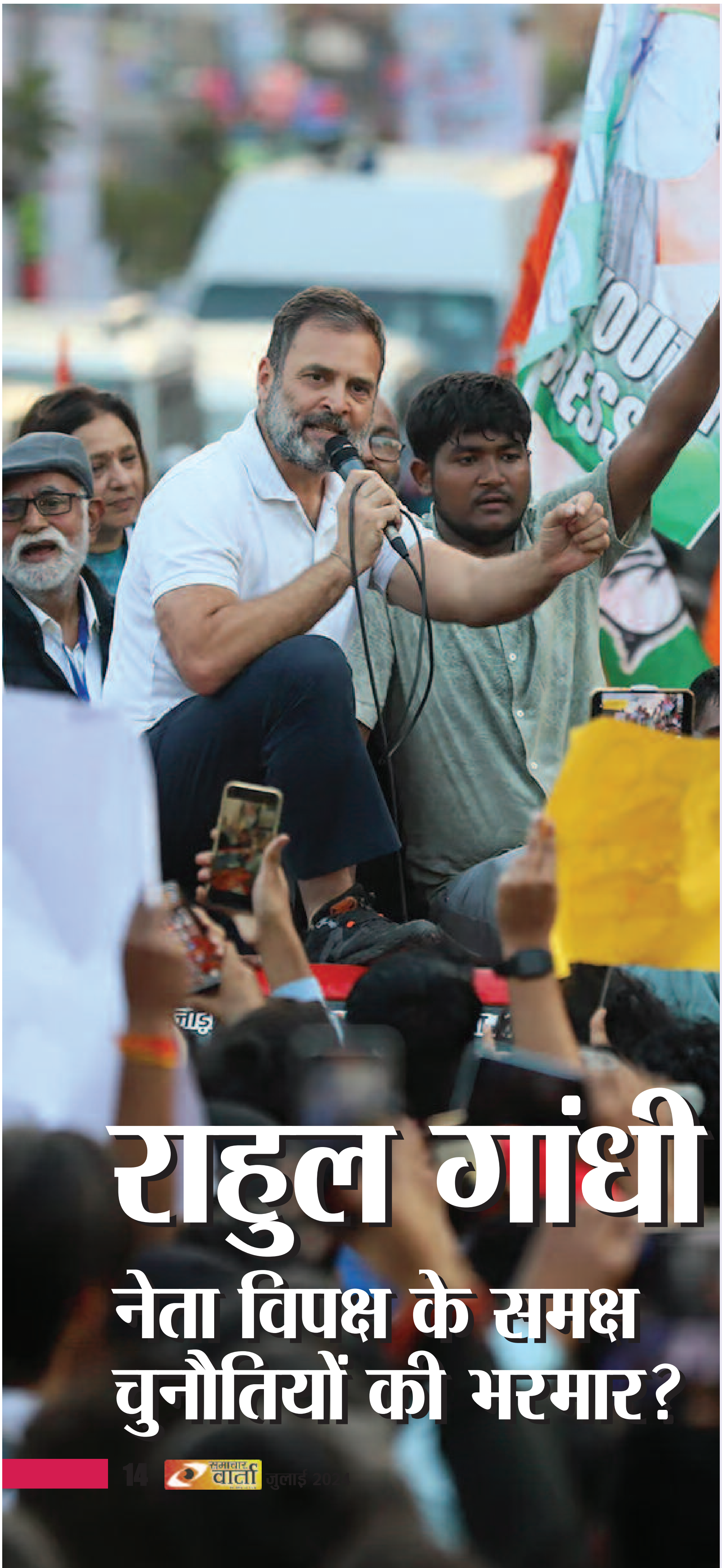

राहुल गांधी

नेता विपक्ष के समक्ष चुनौतियों की भरमार?

कांग्रेस हो या भाजपा, प्रचंड जीत से बौराने की प्रवृति से सभी दलों को तौबा करना होगा। 2024 का जनादेश सभी के लिए सीख जैसा है। कांग्रेस को जनता ने नया जीवनदान दिया है। इसलिए कांग्रेस के सितारे एक बार फिर थोड़े से चमके हैं। पिछली बार मात्र 44 सांसद ही जीतकर संसद पहुंचे थे पर ये आंकड़ा इस दफे 99 तक पहुंचा है। तभी कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के लिए दावेदार हुई है।

● **प्रियव्रत माधव**

16वीं और 17वीं लोकसभा में नबंरों के लिहाज से कांग्रेस बीते 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में इतना पिछड़ गई थी कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद भी नसीब नहीं हुआ। नेता विपक्ष पद की बात तो दूर, पार्टी का भविष्य और अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया था। कम नंबर संख्या के कारण ही संसद में नेता विपक्ष की सीट भी रिक्त रही पर, कहते हैं कि सियासत में चमत्कार की संभावनाएं अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा रहती हैं। किसके सितारे बुलंद हो जाए और किसके अचानक बुझ जाएं? इसका दारोमदार सब कुछ जनता-जर्नादन के मूड और विचारों पर निर्भर रहता है?

बीते 2024 के आम चुनाव में हुआ भी कमोबेश कुछ ऐसा ही? भाजपा 400 पार के नारे के साथ फिर से प्रचंड बहुमत में आने को पूरी तरह आश्वस्त थी लेकिन जनता ने अस्वीकार कर दिया। मौका जरूर दिया, लेकिन आधा-अधूरा? हालांकि, कांग्रेस ने इस बार उम्मीद से कहीं बढ़कर बेहतीन प्रदर्शन कर खुद को लड़ाई में बरकरार रखा। कांग्रेस हो या भाजपा, प्रचंड जीत से बौराने की प्रवृति से सभी दलों को तौबा करना होगा। 2024 का जनादेश सभी के लिए सीख जैसा है। कांग्रेस को जनता ने नया जीवनदान दिया है। इसलिए कांग्रेस के सितारे एक बार फिर थोड़े से चमके हैं। पिछली बार मात्र 44 सांसद ही जीतकर संसद पहुंचे थे पर ये आंकड़ा इस दफे 99 तक पहुंचा है। तभी कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के लिए दावेदार हुई है। अच्छे नंबरों से पास होने का ही नतीजा है

कि नेता विपक्ष के लिए राहुल गांधी के नाम पर ताजपोशी होना विपक्षी धड़े की ओर से मुकर्रर हुआ है पर, जनता का संदेश पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बराबर है? जो जनता के हित में काम करेगा, उसकी जयकार होगी वरना, घमंड़ चकनाचूर करने में देश के मतदाता जरा भी नहीं हिचकेंगे? 2024 के जनादेश ने देश की सियासी तस्वीर पूरी तरह से बदल दी है। चाहे प्रधानमंत्री हों या नेता विपक्ष, सभी से काम की उम्मीद करती है। नेता भी अब समझ गए हैं कि लच्छेदार बातों और हवा-हवाई दावों से अब काम नहीं चलने वाला?

बहरहाल, गठबंधन राजनीति में नेता विपक्ष के पद को पूरे पांच वर्ष तक सुचारू रूप से यथावत रखना भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा? पद पर आसीन होने वाले ओहदेदार के लिए भी चुनौतियों की भरमार रहेंगी। उन्हें हर घड़ी अग्निपरीक्षा से गुजरना होगा। नेता विपक्ष का पद राहुल गांधी की सियासी समझ की भी कठिन परीक्षा लेगा क्योंकि सत्तापक्ष और देश की एक बड़ी आबादी अभी तक उन्हें सियासत का 10वीं पास छात्र ही समझती रही है। दरअसल समझने के कई ताजा उदाहण भी सामने मुंह खोले जो खड़े हैं। राहुल गांधी कई बार अपने सियासी प्रयोगों में विगत वर्षों में असफल हुए हैं इसलिए भी लोगों को थोड़ा बहुत संदेह अब भी है? उनके सियासी इतिहास के पन्ने खोले तो सामने एक विफलता भरी तस्वीर उभरती है कि वह कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी अच्छे से निर्वाह नहीं कर सके, जिसके चलते उन्हें पद छोड़ना पड़ा था। अमेठी से चुनाव भी हारे और अपनी अगुआई में पार्टी को चुनाव लड़ाकर भी ज्यादा कुछ नहीं कर सके। कुल मिलाकर उनके हिस्से में सियासी असफलता की भरमार है पर, इन गुजरे वर्षों में अच्छी बात ये रही, वह लगातार हारने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारे, सियासी मैदान में डटे रहे? खुद को साबित करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जिसमें लोगों का समर्थन हासिल किया। यही कारण है, जनता ने उनपर थोड़ा भरोषा जताया है।

खैर, राजनीति में असफलता ज्यादा मायने नहीं रखती, कोई भी हार सकता है। इसलिए ये पुरानी और बेजान बातें ही हैं। सियासत ऐसा अखाड़ा है जहां अच्छे से अच्छा खिलाड़ी चित हुआ है। ताजा उदाहरण मौजूदा लोकसभा चुनाव का परिणाम है जिसमें बड़े से बड़े शूरमा धराशाही हो गए हैं। अपने राजनीतिक करियर में राहुल गांधी पहली मर्तबा कोई संसदीय ओहदा संभालने जा रहे हैं। 18वीं लोकसभा में वह नेता विपक्ष की भूमिका में होंगे, जिसे इंडिया गठबंधन के तकरीबन सभी प्रमुख नेताओं ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। राहुल की उम्मीदवारी की स्वीकृति के लिए प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को कांग्रेस की ओर से बीती 25 जून की देर शाम को अर्जी भी भेज दी गई है। हालांकि उनके इस पद को लेकर कोई अड़चन या अड़गा इसलिए नहीं लगेगा, क्योंकि संसदीय परंपरा और नियमानुसार नेता विपक्ष के लिए किसी भी दल के पास दस फीसदी सांसद होने चाहिए, जिसमें कांग्रेस सफल है। नेता विपक्ष का पद कांग्रेस को दस साल बाद नसीब होगा।

राहुल नेता विपक्ष बनने वाले गांधी परिवार से तीसरे सदस्य होंगे। उनके पहले उनके पिता तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सांसद माता सोनिया गांधी रह चुकी हैं। प्रतिपक्ष भारतीय संसद के दोनों सदनों में, प्रत्येक में आधिकारिक विपक्ष का नेतृत्वकर्ता होता है। इसलिए नेता विपक्ष का ओहदा अपने आप में बहुत मायने रखता है। प्रधानमंत्री जैसी एक तिहाई शक्तियां उन्हें प्रदान होती हैं। सुविधाएं केंद्रीय मंत्री से कहीं बढ़ कर दी जाती हैं।

तनख्वाह भी तीन लाख रुपए से ऊपर होती हैं। इसके अलावा नेता विपक्ष ईडी निदेशक, सीबीआई प्रमुख, सीवीसी जैसे उच्चस्थ पदों की नियुक्ति में सहभागी होता है। प्रधानमंत्री को नियमानुसार नेता विपक्ष की राय लेनी अनिवार्य होती है। नेता विपक्ष अभिलेखा समिति का भी प्रमुख रहता है जो सरकार के प्रत्येक निर्णयों और खर्चों पर निगाह रखता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपने तीसरे कार्यकाल में जो भी बड़े निर्णय लेंगे या संवैधानिक नियुक्तियां करेंगे ,उसमें नेता विपक्ष की भूमिका रहने वाले उस नेता की राय लिया करेंगे, जिन्हें चुनाव में उन्होंने ये भी कह दिया था कि 'कौन राहुल'? इसलिए इस बार की संसदीय प्रक्रिया बहुत दिलचस्प और टकराव भरी होने वाली है। इसमें चुनौती राहुल गांधी के समझ सबसे ज्यादा रहेंगी, क्योंकि जनता उनके दमखम को नेता विपक्ष के तौर पर परखेगी और भविष्य की राजनीति में उनके कद को तय करेगी।

मोदी जी के नेतृत्व भारत बनेगा विश्व गुरु

जयप्रकाश निषाद

राजीव निशाना

निषाद समाज की आवाज बनकर उभरे जय प्रकाश निषाद, योगी जी और मोदी जी की कार्यशैली के प्रभावित होकर बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए, उत्तर प्रदेश में मंत्री पद से राज्यसभा के सांसद तक का सफर तय किया, आज जय प्रकाश निषाद किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब इनको राजनीति में पैर जमाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा, पहली बार चुनाव लड़ने का मौका बसपा ने 2007 में मनीराम विधानसभा से दिया था इस चुनाव में भीतरी घात के चलते तीसरे स्थान पर

रहे, तब 2008 से 2009 तक बसपा की सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए थे भारत के उत्तर प्रदेश की सोलहवीं विधानसभा में विधायक रहे हैं। 2012 उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की चौरी-चौरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, (निर्वाचन संख्या-326) से चुनाव जीता था। विधायक बनने के बाद जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में विकास कार्य किये, और क्षेत्रीय जनता के दिलों में अपनी जगह बनाई ! विधायक काल के समय वह बसपा की कुछ गलत नीतियों से परेशान थे जो उनका बसपा छोड़ने का कारण बना ! वह योगी जी और मोदी जी की कार्यशैली से काफी प्रभावित थे जिस वजह से उन्होंने भाजपा में जुड़कर जनहित में कार्य करने का निर्णय लिया ! फरवरी 2018 में माननीय योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी एक सभा में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की

जाएगी। वे इस समय भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं। उन्हें हाल ही में पूर्वांचल विकास बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है।वर्तमान राजनीति में जयप्रकाश निषाद मोदी जी की कार्यशैली से काफी प्रभावित है और वह मानते है भारत को विश्व गुरु केवल मोदी जी के नेतृत्व में ही बनाया जा सकता है , आज मोदी जी ने विश्व में भारत को अलग पहचान दिलाई है जिस वजह से प्रत्येक भारतवासी स्वयं को गौरान्वित महसूस करता है देश आर्थिक,सामाजिक व धार्मिक रूप से काफी मजबूत हुआ है, मोदी जी ने देश वासियों के लिए करीब 26 महत्वपूर्ण योजनाए चलाई है , जो जन धन योजना, कौशल भारत मिशन, मेक इन इंडिया, मिशन स्वच्छ भारत, सांसद आदर्श ग्राम योजना, श्रमेव जयते योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हृदय योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उजाला योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, कुल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, स्मार्ट सिटी पहल, अमृत रणनीति, डिजिटल इंडिया मिशन, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना,सॉवरेन गोल्ड बांड योजना, उदय, स्टार्ट-अप इंडिया, सेतु भारतम योजना, उठो भारत, ग्रामोदय से भारत उदय, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, नमामि गंगे योजना, सतत योजना है !

इनके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है पीएम किसान योजना देश भर के सभी पात्र किसान परिवारों को हर चार महीने में 2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में 6000 रुपये की वार्षिक आय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अनुसार, एक परिवार में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल होते हैं। 2,000 रुपये की धनराशि सीधे किसानों/किसान परिवार के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।

मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जरिए लोगों को बेटियों की शिक्षा के प्रति जागरूक किया ताकि बेटियां शिक्षित होकर अपने सक्षम बन सके, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोडो लोगों को अपने घर दिए, जन -धन योजना के तहत सभी को बैंकिंग से जोड़ा, कौशल भारत के जरिए युवाओं को कुशल पेशेवर बनाने पर जोर दिया ताकि युवा स्वरोजगार में अपनी भागीदारी बढ़ा सके, मेक इन इंडिया के द्वारा जोर दिया भारतवासी जो वस्तुएं प्रयोग करते है उनका निर्माण भारत में ही हो, मिशन स्वच्छ भारत से सभी को स्वच्छ रहना और अपने आस पास के स्थान साफ सुथरे रखने सिखाए ताकि लोग गंदगी की वजह से बीमार काम पड़े, उज्ज्वला योजना के तहत लाखों महिलाओं को रसोई गैस उपलब्ध करवाई ! इनके अलावा मछुआरों के लिए मोदी जी ने मत्स्य सम्पदा योजना की शुरूआत 20 हजार करोड़ से की, जिसका मछुआरों को सीधा लाभ मिला, नीट में ओबीसी समाज को मोदी जी द्वारा 27 प्रतिशत की भागीदारी दी गयी, गाँव देहातो में सबसे ज्यादा परेशानी का सामना महिलाओं को खुले में शौच करते समय करना पड़ता था, जिस परेशानी को मोदी जी ने समझा ओर भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाया, घर घर तक शौचालय बनवाएं !इसी तरह मोदी जी की दूरदर्शी योजनाओं से देशवासियों को लाभ हुआ है और वह दिन दूर नहीं जब मोदीजी के नेतृत्व में भारत विश्वगुरु बने।

राहुल गांधी का झूठ पकड़ा गया मोदी राज में बढ़ रही सेना की ताकत

प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जताई गई चिंताओं का हवाला तक सदन में दिया, जिसके बाद कहना होगा कि राहुल गांधी के संसद में नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी बोले गए झूठ से यह साफ हो गया है कि कांग्रेस अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।

रविन्द्र कुमार

सेना को लेकर भ्रम फैलाते हुए अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी ने जो झूठा नैरेटिव शहीद के सम्मान और मिलनेवाली राशि को लेकर रचा, उसका सच अब दुनिया के सामने है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कही यह बात भी पूरी तरह से सत्य साबित हो गई कि कांग्रेस का अपना एक इकोसिस्टम है, जिसके लिए देश से ऊपर सिर्फ उसका अपना हित है, यदि भारत का नुकसान होता है तो उससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जताई गई चिंताओं का हवाला तक सदन में दिया, जिसके बाद कहना होगा कि राहुल गांधी के संसद में नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी बोले गए झूठ से यह साफ हो गया है कि कांग्रेस अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।

यहां जिस परिवार और अग्निवीर की शहीदी को आधार बनाकर राहुल गांधी, सदन में प्रधानमंत्री मोदी एवं एनडीए सरकार से प्रश्न पूछ रहे थे, वे सभी प्रश्न उस परिवार के साथ सेना से आए स्पष्टीकरण के बाद पूरी तरह से असत्य साबित हुए हैं। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान यह सभी ने देखा भी कि किस तरह से राहुल, केंद्रीयमंत्री राजनाथ सिंह को झूठा ठहरा रहे थे। राहुल का यह आरोप बहुत साफ था कि रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने 'अग्निवीर' के जान गंवाने पर उनके परिवार को आर्थिक मदद मिलने के बारे में संसद के भीतर झूठ बोला है, इसलिए रक्षामंत्री को संसद, देश और सेना से माफी मांगनी चाहिए। जिसके तुरंत बाद रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का जवाब भी सामने आया, उन्होंने साफ शब्दों में बताया, सीमाओं की रक्षा करते हुए या युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले अग्निवीर के परिवार को एक करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। वहीं, जिस अग्निवीर की बात राहुल कर रहे थे, उसके परिवार ने भी स्वीकार्य किया है कि उन्हें राशि मिल चुकी है, अभी और मिलेगी।

रक्षा मंत्रालय के एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के अतिरिक्त लोक सूचना महानिदेशालय का कहना भी यही है, कुल देय राशि में से, अग्निवीर अजय के परिवार को पहले ही 98.39 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। अग्निवीर योजना के प्रावधानों के अनुसार लागू लगभग 67 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और अन्य लाभ, पुलिस सत्यापन के बाद अंतिम खाता निपटान पर भुगतान किए जाएंगे। देय कुल राशि लगभग 1.65 करोड़ रुपये होगी। अतः यहां इससे एक बात तो साफ हो गई कि राहुल गांधी अपने फायदे के लिए झूठ की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ कहने भर के लिए वह संविधान को हाथ में उठाए घूमते हैं और समानता की दुहाई देते हैं। किंतु

वास्तव में ऐसा है नहीं। प्रधानमंत्री मोदी इसलिए आज कांग्रेस से पूछ भी रहे हैं कि वह ऐसा किसके फायदे के लिए कर रही है ? जबकि उनकी सरकार भारतीय सेना को युद्ध के लिए सशक्त बनाने में जुटी है। सीडीएस (प्रमुख सेना अध्यक्ष) के पद के सृजन के बाद तीनों सेना में समन्वय मजबूत हुआ है और थियेटर (मोर्चा) कमान की दिशा में भी काम हो रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना भी सही है, "इंदिरा गांधी की सरकार ने सेना एक रैंक एक पेंशन प्रणाली को समाप्त किया था। दशकों तक कांग्रेस ने ऊसे फिर से लागू होने नहीं दिया, एक बार तो चुनाव से पहले कांग्रेस के नेतृत्ववाली सरकार ने 500 रुपये दिखाकर सेना के कमांडरों को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया था, जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने सत्ता में आने के बाद एक रैंक एक पेंशन की प्रणाली को फिर से लागू कर दिया। यह कांग्रेस ही है जो राफेल विमानों की खरीद का विरोध कर रही थी। कांग्रेस सरकार में लड़ाकू विमान नहीं खरीदे गए, जब हमने खरीदने की कोशिश की, तो कांग्रेस हर तरह की साजिश करने पर उतर आयी। वास्तव में रक्षा सुधारों के प्रयासों को कमजोर करने का यह षड्यंत्र है।" प्रधानमंत्री मोदी याद दिलाते हैं, "वह भी वक्त था, जब कांग्रेस के जमाने में हमारी सेनाओं के पास बुलेटप्रूफ जैकेट भी नहीं होते थे।" सवाल यह है कि कांग्रेस ऐसा किसके फायदे के लिए कर रही है। अग्निवीर योजना को मुद्दा बनाने को लेकर कांग्रेस पर सेना का मनोबल तोड़ने का प्रयास करने का आरोप भी प्रधानमंत्री मोदी का है । बहुत हद तक प्रधामंत्री नरेन्द्र मोदी के इस आरोप में दम है, क्योंकि जिस प्रकार का नैरेटिव कांग्रेस गढ़ रही है उसका मूल उद्देश्य यही है कि देश के नौजवान सेना में न जाएं। किंतु देश देख रहा है, कि कैसे मोदी राज में भारतीय सेनाएं हर मोर्चे पर अधिक सशक्त हुई हैं। स्वयं अमेरिका की गुप्त रिपोर्ट में भी यही दावा किया गया है। यह रिपोर्ट कहती है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में भारत विश्व में लगातार अपनी धमक बना रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के शीर्ष खुफिया एजेंसी में अधिकारी निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूस ने अमेरिकी संसद को बताया भी कि कैसे भारतीय सेना लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है।

अमेरिका के इस बड़े अधिकारी ने सशस्त्र सेवा समिति और खुफिया उपसमिति के सदस्यों को यह जानकारी दी है कि भारत ने जी-20 के आर्थिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर खुद को एक वैश्विक अगुआ के रूप में प्रदर्शित किया है और पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में पीआरसी (पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना) की गतिविधि का मुकाबला करने के लिए स्वयं को सक्षम साबित किया है। भारत ने प्रशिक्षण और रक्षा बिक्री के माध्यम से फिलीपीन जैसे क्षेत्रीय दक्षिण चीन सागर दावेदारों के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में उन्नत साझेदारी की है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस व जापान के साथ अपने सहयोग को और मजबूत किया है।

भारत ने चीन से प्रतिस्पर्धा करने और रूसी उपकरणों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए कई कदम उठाए। भारत ने स्वदेशी विमानवाहक पोत का समुद्री परीक्षण किया और प्रमुख रक्षा प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर कई पश्चिमी देशों के साथ बातचीत भी की है और इसके लिए सबसे आवश्यक रक्षा बजट में भारी बढ़ोत्तरी की है। जो यह बताने के लिए पर्याप्त है कि वास्तव में मोदी सरकार के रहते सेना को हर तरीके से मजबूती प्रदान करने में जिस धन का सबसे अधिक उपयोग होना है, यदि उसकी कमी नहीं रहेगी तो सेना हर मोर्चे पर अपने को सशक्त रूप से साबित करती रहेगी, जोकि वह आज कर पा रही है।

सरकार का 'अग्निपथ'

> केंद्र सरकार ने 10 अलग-अलग मंत्रालयों के सचिवों को अग्निपथ योजना की समीक्षा का कार्य सौंपा है। सचिवों का यह समूह अग्निपथ योजना के जरिए सैनिकों की भर्ती को और अधिक आकर्षक बनाने के तरीके सुझाएगा। इस पहल के जरिए यदि अग्निपथ योजना में कोई कमी हो तो उसे भी दूर किया जा सकता है।

● **विशाल कश्यप**

नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना शुरू की गयी थी। इस योजना के तहत भर्ती भी की गयी लेकिन इसके कुछ प्रावधानों को लेकर उसी समय से विवाद चल रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में सेना की अग्निवीर योजना को चुनावी मुद्दा बनाया गया। उसका विरोध विशेष रूप से कांग्रेस के राहुल गांधी कर रहे थे लेकिन जब बिहार में नीतीश कुमार जद(यू) और कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे थे, तब उन्होंने भी अग्निपथ योजना का विरोध किया था। इसके बाद बिहार की राजनीति में जबर्दस्त बदलाव आया और नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनायी। भाजपा के नेतृत्व वाले राजद (एनडीए) के साथ ही नीतीश कुमार की पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ी है। संयोग से इस बार भाजपा को सिर्फ 240 सांसद मिल पाये। इसलिए एनडीए के सहयोगी दलों का अप्रत्यक्ष रूप से दबाव स्वाभाविक है। नीतीश कुमार ने नयी सरकार बनने से पहले ही कहा था कि अग्निपथ योजना की समीक्षा होनी चाहिए। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और पूर्व सेनाध्यक्ष इस योजना को सेना के हित में बता रहे थे लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के चलते अग्निपथ योजना की समीक्षा की जा रही है। केन्द्र सरकार ने 10 मंत्रालयों के सचिवों को इस योजना की समीक्षा का दायित्व सौंपा है। इस योजना का नया स्वरूप क्या होता है, इसके लिए प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी। मोदी ने राजनाथ सिंह को ही फिर से रक्षामंत्रालय सौंपा है। इन्हीं के विभाग का मामला है।

केंद्र सरकार ने 10 अलग-अलग मंत्रालयों के सचिवों को अग्निपथ योजना की समीक्षा का कार्य सौंपा है। सचिवों का यह समूह अग्निपथ योजना के जरिए सैनिकों की भर्ती को और अधिक आकर्षक बनाने के तरीके सुझाएगा। इस पहल के जरिए यदि अग्निपथ योजना में कोई कमी हो तो उसे भी दूर किया जा सकता है। गौरतलब है कि अग्निपथ योजना के तहत सेना में अग्निवीरों को भर्ती किया जाता है। यह भर्ती चार साल के लिए होती है। इस दौरान नियमित वेतन के अलावा चार वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर अग्निवीर सैनिकों को लगभग 12 लाख रुपए मिलते हैं। एक निश्चित संख्या में अग्निवीरों को स्थायी सेवा का अवसर भी मिलता है। अब इस योजना की समीक्षा की जा रही है। इसमें कई नए सुधार और नए पहलू जोड़े जा सकते हैं।

बताया जा रहा है कि शीघ्र ही सचिवों का यह समूह अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा। माना जा रहा है सचिवों का समूह अग्निपथ योजना के अंतर्गत वेतन भत्तों में बढ़ोतरी के साथ कुछ अन्य लाभ बढ़ाने का प्रस्ताव दे सकता है। हालांकि अभी इस संबंध में कोई भी औपचारिक या अनौपचारिक विचार सामने नहीं आया है। यह महत्वपूर्ण समीक्षा सरकार के प्रथम 100 दिवसीय एजेंडे में शामिल

है। जानकारी के मुताबिक, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का यह समूह 15-16 जून तक इस संबंध में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। भारत सरकार के ये वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रधानमंत्री कार्यालय में अपनी रिपोर्ट के आधार पर विस्तृत प्रस्तुति देंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री कार्यालय में यह प्रस्तुति कब दी जाएगी, इसकी तिथि निश्चित नहीं है।

उल्लेखनीय है कि भारतीय सेना ने भी अग्निपथ योजना की समीक्षा का कार्य शुरू किया है। जानकारी के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया पर सेना एक आंतरिक मूल्यांकन कर रही है। सरकार ने भारतीय सशस्त्र बलों में जवानों की अल्पकालिक भर्ती के लिए जून 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की थी। अग्निवीर योजना शुरूआत से ही विपक्ष के निशाने पर रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष द्वारा इसे व्यापक स्तर पर उठाया गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा व राजस्थान जैसे कई राज्य ऐसे हैं जहां सेना में भर्ती होने वाले युवकों की संख्या अच्छी खासी है। यही कारण है कि चुनाव उपरांत एनडीए के कुछ घटक दलों व उनके नेताओं ने भी अग्निपथ योजना की समीक्षा किए जाने की बात कही थी। सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए पिछले साल अग्निपथ योजना शुरू की गई थी। इस योजना का देशभर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं अग्निपथ योजना की वैधता को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती भी दी गई थी, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।

अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों की तीन सेवाओं यानी थल सेना, जल सेना और वायु सेना में भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है। इस योजना की घोषणा 16 जून 2022 को की गई थी। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले जवानों को 'अग्निवीर' के नाम से जाना जाएगा। 10वीं पास उम्मीदवार अग्निवीर जनरल ड्यूटी पद के लिए आवेदन करने के पात्र माने जाएंगे। उम्मीदवार का 10वीं की परीक्षा 45 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। सभी विषयों में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करना होगा। अग्निपथ योजना के लिए 17 से 23 वर्ष के उम्मीदवार योग्य माने जाएंगे। इस योजना के तहत 25 प्रतिशत युवाओं की सेवा नियमित कर दी जाएगी। अग्निवीर पद के लिए जिन योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा उन्हें पहले वर्ष में- 30,000, दूसरे वर्ष में- 33,000, तीसरे वर्ष में-36,500 और चैथे वर्ष में- 40,000 रुपये मिलेंगे। अग्निवीर योजना के तहत उम्मीदवारों का चयन रैली, फिजिकल टेस्ट और लिखित परीक्षा के जरिए किया जाएगा। अग्निवीर योजना के तहत इच्छुक उम्मीदवारों के लिए देश भर में करीब 200 सेंटरों पर पहले कॉमन ऑनलाइन टेस्ट आयोजित होता है। इसी योजना को लेकर बिहार में छात्रों के उग्र होते आंदोलन के बाद जेडीयू ने छात्रों और इस आंदोलन से खुद को अलग कर लिया था। नीतीश सरकार में जेडीयू के विद्युत मंत्री विजेंद्र यादव से जब सवाल पूछा गया कि छात्र अग्निपथ योजना को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आप केंद्र और राज्य में भाजपा के साथ गठबंधन सरकार चला रहे है। इस पर मंत्री ने दो टूक जवाब दिया कि इसमें राज्य सरकार क्या कर सकती है? यह मामला केंद्र का है। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार में जमकर विरोध हो रहा था। सेना भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थियों की ओर से राज्य के कई जिलों में हिंसक विरोध-प्रदर्शन हुआ है। इस दौरान बीजेपी नेताओं के घरों और पार्टी के दफ्तरों को भी निशाना बनाया गया। इस हिंसक प्रदर्शन को लेकर बिहार एनडीए के दो दलों बीजेपी और जेडीयू में टकराव हो गया था। बिहार बीजेपी ने हिंसक प्रदर्शन को प्रशासन की विफलता करार देते हुए इशारों में सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा तो वहीं जेडीयू ने पलटवार करते हुए सवाल किया कि बीजेपी शासित राज्यों में प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों पर गोलियां क्यों नहीं चलवाते। अब मोदी के नेतृत्व में बनी तीसरी सरकार में भी नीतीश ने इस पर सवाल उठाया है।

मंत्रिमंडल में झलकी निश्चिंतता

● **राजेश मेहरा**

इसमें कोई संदेह नहीं कि नरेन्द्र दामोदर दास मोदी हर परिस्थिति में धैर्य को बरकरार रखते हैं। एक समय था जब दिल्ली में किरण वेदी को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया था और भाजपा दिल्ली में बुरी तरह पराजित हुई थी।

मोदी ने उस समय भी धैर्य रखा और भविष्य में भाजपा उनके ही नेतृत्व में शिखर पर पहुंची है। इस बार जब 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए तो नतीजे भाजपा के अनुकूल नहीं रहे। यहां तक कि यूपी जैसे राज्य में, जहां वाराणसी से नरेन्द्र मोदी स्वयं प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अयोध्या में निर्मित नव्य-भव्य, राम मंदिर को भारत की झांकी बना दिया गया था, वहां भाजपा को 80 में से सिर्फ 33 सांसद मिल पाये।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ कोई उंगली उठाता, उससे पहले ही मोदी ने उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा 'किसी प्रकार की चिंता मत करो, ये सब होता ही रहता है।' इसके बाद एनडीए की शक्ल इस बार बदल गयी। पहले भाजपा को ही स्पष्ट बहुमत दिलाने वाले सांसद मिल जाते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 240 सांसद मिल पाये। बहुमत के लिए 272 सांसद चाहिए। इस प्रकार एनडीए के सहयोगी दलों विशेषकर नीतीश कुमार की जद(यू) और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी पर निर्भरता बढ़ गयी थी और कयास लगाये जा रहे थे कि मोदी के मंत्रिमंडल पर इसका प्रभाव पड़ेगा लेकिन मोदी का धैर्य यहां भी बरकरार रहा। मंत्रिमंडल गठन में किसी प्रकार का दबाव नहीं दिखा। सभी महत्वपूर्ण विभाग भाजपा के पास हैं इतना ही नहीं सभी मंत्रियों को 100 दिन का लक्ष्य भी बता दिया गया है। मंत्रियों ने भी इसका संकेत दिया है। भाजपा के संकल्प पत्र में 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाने का वादा किया गया था। कैबिनेट की पहली बैठक में ही इसकी घोषणा कर दी गयी है। राजग में चार दर्जन से ज्यादा राजनीतिक दल शामिल हैं लेकिन प्राथमिकता भाजपा के संकल्प पत्र को ही दी गयी है।

भाजपा में मोदी के बाद कद्दावर नेता समझे जाने वाले अमित शाह को ही फिर से गृहमंत्री का दायित्व मिला है। गृह मंत्रालय के अलावा पिछली बार की तरह सहकारिता मंत्रालय भी दिया गया। नये कार्यकाल में अमित शाह की प्राथमिकताओं में पिछले वर्ष पारित तीन अपराध कानूनों को अमल में लाना है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को इसी साल 1 जुलाई से लागू हो गया। अमित शाह कहते हैं कि हमने पिछले कार्यकाल में सहकारिता क्षेत्र के विकास की नींव रखी थी, अगले पांच वर्षों में उन्हें जमीनी स्तर पर पहुंचाएंगे। अमित शाह कहते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत से आतंकवाद और उग्रवाद को मिटाएंगे।

इसी प्रकार मोदी ने अपने पूर्व विदेश मंत्री एस. जयशंकर पर फिर से भरोसा जताया और दुबारा कार्यभार संभालने के बाद वह कहते हैं कि पाकिस्तान के संरक्षण्सा में सीमा पार से जो आतंकवाद की चुनौती है, उससे निपटने के और सार्थक प्रयास किये जाएंगे। कीर्तिवर्द्धन सिंह और पवित्र मार्गरेटा को जयशंकर का सहयोगी (राज्यमंत्री) बनाया गया है। जयशंकर कहते हैं कि

भारत प्रथम व वसुधैव कुटुंबकम भारतीय विदेश नीति के दो मार्गदर्शक सिद्धांत होंगे। पीएम मोदी ने निर्मला सीतारमण को फिर से वित्त विभाग सौंपा है। भारत को विकसित देश बनाने में अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान होगा। अभी हम विश्व की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं लेकिन निर्मला सीतारमण अर्थव्यवस्था को तीसरे स्थान पर लाएंगी।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान इस बार शानदार वोटों से जीते हैं। चैहान को केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालयों का कार्यभार सौंपा गया है। रामनाथ ठाकुर व भगीरथ चैधरी उनके सहयोगी राज्यमंत्री बनाये गये हैं। किसान कल्याण पीएम मोदी की शीर्ष प्राथमिकता में है। अश्विनी वैष्णव सबसे ज्यादा मंत्रालय संभाल रहे हैं। उनके पास रेलवे, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रसारण मंत्रालय का दायित्व है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बार दूर संचार मंत्री बनाया गया है। यूपीए सरकार में भी वह इस मंत्रालय की बागडोर संभाल चुके हैं। इस प्रकार बिना किसी दबाव के नरेन्द्र मोदी ने मंत्रिमंडल का गठन कर और उन्हें विभाग आवंटित कर यह साबित कर दिया कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोना चाहिए।

नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली तीसरी सरकार में अधिकांश प्रमुख कैबिनेट मंत्रियों ने पिछली भाजपा सरकार में उनके पास रहे विभागों को बरकरार रखा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की लंबी राजनीतिक पारी खेलने वाले राजनाथ सिंह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में रक्षा मंत्री बनाए गए हैं।

नितिन गडकरी को भी उनके पुराने मंत्रालय में ही बरकरार रखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बनाया गया है। सरकार के अन्य मंत्रियों की बात करें तो भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं रसायन एवं उर्वरक, शिवराज सिंह चैहान को कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं. अश्विनी वैष्णव को रेलवे एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के साथ-साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया है. इसके अलावा भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति और पर्यटन, अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास, किरेन रिजिजू को संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामले, हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, मनसुख मंडाविया को श्रम और रोजगार एवं युवा मामले और खेल, जी. किशन रेड्डी को कोयला और खान, चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और सीआर. पाटिल को जलशक्ति मंत्री बनाया गया है।

नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे, अन्य सभी विभाग रहेंगे, जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए। मनोहर लाल खट्टर को शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री, एचडी कुमारस्वामी को भारी उद्योग और स्टील मंत्री, पीयूष गोयल को कॉमर्स एवं इंडस्ट्री मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री, जीतनराम मांझी को सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग, राजीव रंजन (ललन सिंह) को पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, किरेन रिजिजू को संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्री, मनसुख मांडविया को श्रम और रोजगार, युवा मामले और खेल मंत्री, जी किशन रेड्डी को कोयला और खान मंत्री, चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग मंत्री, सीआर पाटिल जल शक्ति मंत्री, सबानंद सोनोवाल को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री, वीरेंद्र खटीक को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, राममोहन नायडू को सिविल एविएशन मंत्री, भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत को कल्चर और टूरिज्म मंत्री, प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, जुएल उरांव को जनजातीय मामलों के मंत्री, अन्नपूर्णा देवी यादव को महिला एवं बालविकास मंत्री, गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्री बनाया गया है। मंत्रिमंडल में कहीं भी दबाव नहीं झलक रहा है।

वर्ष 2030 तक होगी 60 फीसदी आबादी अस्वस्थ

● **गोविन्द जोशी**

हाल ही में शारीरिक गतिविधियों के संबंध में लैंसेट ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के तथ्य अत्यंत चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट में भारतीय व्यस्कों के स्वास्थ्य की स्थिति को चिंताजनक बताया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वयस्कों में अपर्याप्त शारीरिक गतिविधियों का प्रतिशत वर्ष 2000 के 22.3 से बढकर वर्ष 2022 में 49.4 हो गया बताया गया है और यह भी कहा गया है कि यदि इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वर्ष 2030 तक 60 फीसदी आबादी अस्वस्थ होगी। यह भारत के लिहाज से अत्यंत चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए क्योंकि पर्याप्त शारीरिक गतिविधियां नहीं होने से बीमारियों का खतरा बना रहेगा। यह अत्यंत विचारणीय होने के साथ ही अत्यंत गंभीर है कि भारत की आधी वयस्क आबादी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के शारीरिक गतिविधियों संबंधी दिशा-निदेर्शों को पूरा नहीं करती है। यानी शारीरिक तौर(फिजीकली फिट) पर पूरी तरह फिट नहीं है। बताया गया है कि पुरुषों (42 फीसदी) के मुकाबले महिलाएं (57 फीसदी) शारीरिक गतिविधियों के मामले में ज्यादा निष्क्रिय हैं। कहना गलत नहीं होगा कि भारत में शारीरिक श्रम करने में लोग काफी आलसीपन दिखाते हैं।

रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि वैश्विक स्तर पर लगभग एक तिहाई लोग (31.3 प्रतिशत) शारीरिक श्रम पर्याप्त रूप से नहीं करते। रिपोर्ट में पाया गया कि ये आंकड़ा वर्ष 2010 के मुकाबले और बढ़ गया है। उस समय के दौरान दुनिया भर में अपर्याप्त रूप से शारीरिक गतिविधि में संलग्न 26.4 प्रतिशत लोग थे, जो अब पांच प्रतिशत अधिक है। दरअसल आज हमारी जीवनशैली में आमूलचूल परिवर्तन आ गये हैं और हमारे देश की आबादी बैठे-बैठे काम करने की प्रवृत्ति की ओर लगातार बढ़ रही है। एक समय था जब ऐसा नहीं था और शारीरिक श्रम पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाता था। बढ़ते मशीनीकरण, आधुनिकीकरण के कारण ऐसा संभव हुआ है। पहले के जमाने की तुलना में हमारे कामकाज के पैटर्न में बदलाव आ गये हैं और आज हर कोई स्क्रीन को अधिक समय दे रहे हैं।

पर्यावरण में भी आमूलचूल परिवर्तन आए हैं। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव भी हमारी जीवनशैली पर पड़ा है। हम वाहनों पर निर्भर हो गये हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान

लैंसेट ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट

द लैंसेट डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी जर्नल में प्रकाशित 2023 इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च-इंडिया डायबिटीज के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि 2021 में भारत में 101 मिलियन लोग मधुमेह से पीड़ित थे और उसी वर्ष लगभग 315 मिलियन लोगों को हाई बीपी था।

में महिलाओं में अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि चिंता का विषय है हालांकि, हमारे पड़ोसी बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में महिलाएं ज्यादा सक्रिय हैं। इस संबंध में विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाओं में निष्क्रियता के लिए घर के कामों में उनकी ज्यादा भागीदारी जिम्मेदार है। इससे उन्हें खुद पर ध्यान देने का कम समय मिलता है। क्या यह सोचनीय व गंभीर नहीं है कि अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि (फिजीकल एक्टिविटी) के मामले में हमारा देश भारत 195 देशों में 12वें पायदान पर है ? दुनिया भर में, करीब एक तिहाई (31 प्रतिशत) वयस्क यानी कि करीब 1.8 बिलियन लोगों ने 2022 में शारीरिक गतिविधि के रिकमेंडेड लेवल(अनुशंसित स्तर) को पूरा नहीं किया। सबसे चिंता की बात यह है कि भारतीय वयस्कों में फिजिकली इनएक्टिव होना साल 2000 में 22.3 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर 2022 में 49.4 प्रतिशत पहुंच गया। इसका मतलब यह है कि हमारी आबादी का 60 प्रतिशत हिस्सा 2030 तक शारीरिक रूप से निष्क्रिय हो जाएगा।वर्ल्ड हेल्थ आगेर्नाइजेशन(डब्ल्यू एच ओ) के मुताबिक, अगर कोई भी वयस्क हफ्ते में 150 मिनट से कम और किसी किशोर की शारीरिक गतिविधि 60 मिनट से कम है तो उसकी शारीरिक गतिविधि को अपर्याप्त माना जाएगा। ऐसे लोगों को योग और एक्सरसाइज पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। डब्लूएचओ की सिफारिश के मुताबिक, सभी वयस्कों के लिए हफ्ते में कम से कम 150 से 300 मिनट की मीडियम एरोबिक एक्टिविटी जरूरी है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि शारीरिक निष्क्रियता वाले वयस्कों में दिल की बीमारियों जैसे दिल का दौरा, स्ट्रोक, टाइप 2 शुगर, मनोभ्रंश और ब्रेस्ट और कोलन कैंसर का खतरा ज्यादा रहता है।

द लैंसेट डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी जर्नल में प्रकाशित 2023 इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च-इंडिया डायबिटीज (क्ठटफ क्ठउक्रअइ) के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि 2021 में भारत में 101 मिलियन लोग मधुमेह से पीड़ित थे और उसी वर्ष लगभग 315 मिलियन लोगों को हाई बीपी था। अध्ययन के अनुसार, इसके अलावा 254 मिलियन लोग मोटापे से ग्रस्त हैं तथा 185 मिलियन लोगों में एलडीएल या 'खराब' कोलेस्ट्रॉल का स्तर उच्च है। पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा शारीरिक निष्क्रियता एशिया-प्रशांत क्षेत्र (48 प्रतिशत) और दक्षिण एशिया (45 प्रतिशत) सामने आई है. अन्य क्षेत्रों में निष्क्रियता का स्तर पश्चिमी देशों में 28 प्रतिशत से लेकर 14

प्रतिशत तक है। रिसर्चर्स का अनुमान है कि यदि ऐसे ही हालात बने रहे तो वो दिन दूर नहीं जब वर्ष 2030 तक करीब 60 प्रतिशत एडल्ट फिजिकली अनफिट हो जाएंगे। रिसर्च में ये भी सामने आया है कि 60 साल की उम्र के महिलाएं और पुरुष शारीरिक गतिविधियों में कम एक्टिव हैं। जानकारी देना चाहूंगा कि वर्ष 2019 में ब्लूमबर्ग हेल्थ इंडेक्स के अनुसार विश्व के दस सबसे स्वस्थ देशों में क्रमशः स्पेन, इटली, आइसलैंड, जापान, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, नार्वे और इजरायल शामिल थे। ग्लोबल हेल्थ सेक्युरिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा स्वस्थ देशों में क्रमशः यूनाइटेड स्टेट्स, आस्ट्रेलिया, फिनलैंड, कनाडा, थाइलैंड, स्लोवेनिया,यूके, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और स्वीडन शामिल थे।

वास्तव में मनुष्य की स्वस्थता जीवन प्रत्याशा, अस्पतालों की गुणवत्ता, पर्यावरण, भोजन की पौष्टिकता-पोषकता, जीवनशैली आदि तथ्यों पर निर्भर करती है। अतः इन सब पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। आज भारतीयों का ध्यान योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन पर कम है, भले ही हम योग दिवस मना रहे हैं। हमने दुनिया को योग दिया, लेकिन वास्तव में जितना ध्यान हमें अपने स्वास्थ्य को लेकर देना चाहिए, उतना हम दे नहीं पा रहे हैं। यहां पाठकों को बताता चलूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के 1948 के संविधान में स्वास्थ्य को 'पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति के रूप में' आज हमारी जीवनशैली बदल चुकी है और इसने हमारे स्वास्थ्य को काफी हद तक प्रभावित किया है।

यही कारण है कि आज विशेष रूप से हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह, मोटापा, चयापचय सिंड्रोम, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और कुछ प्रकार के कैंसर हो रहे हैं। हम हमारी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। भागम-भाग भरी जिंदगी में हमारे पास स्वयं के लिए समय नहीं बचा है। आज हमारा ध्यान स्क्रीन टाइम पर ज्यादा है बजाय एक्सरसाइज के। हालांकि, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने साल 2019 में 29 अगस्त को इंदिरा गांधी स्टेडियम में 'फिट इंडिया कैंपेन' भी लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य फिटनेस को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना था, लेकिन हम दैनिक कामकाज में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना ही भूल जाते हैं।

यह विडंबना ही है कि स्वस्थ जीवनशैली के अनेक लाभों के बावजूद, वयस्कों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही ऐसी दिनचर्या का पालन करता है। वास्तव में, संख्या लगातार घट रही है। यह विडंबना ही है कि स्वास्थ्य और जीवनशैली के बीच संबंध के बारे में लोगों में आज बहुत कम जागरूकता है। बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि जीवनशैली में बदलाव पुरानी बीमारियों के उभरने में एक महत्वपूर्ण कारक है जो रुग्णता और मृत्यु दर में वृद्धि का कारण बनता है। कहना गलत नहीं होगा कि 'एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है।' यदि हमारे देशवासी स्वस्थ होंगे तो वे बेहतर सोचेंगे, एक अच्छा वातावरण बनेगा और देश भी विकास के पथ पर तेजी से चल सकेगा। हमें यह चाहिए कि हम अपनी जीवनशैली में योग, ध्यान, फ्री हैंड एक्सरसाइज, प्राणायाम, श्वास व्यायाम, सूर्य नमस्कार, चलना, दौड़ना, एरोबिक्स, जॉगिंग, नृत्य और खेल आदि को शामिल करें। आज हमारे देश में शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की तत्काल आवश्यकता है।

बदलते रहन-सहन और खानपान से बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य चुनौतियों के प्रति लगातार आगाह किया जाता रहा है, लेकिन हम इस ओर ध्यान नहीं देते। आज बदलती जीवनशैली जान पर भारी पड़ रही है। इसके बावजूद सबक लेने को तैयार नहीं। प्रतिस्पर्धी दौर में सब एक-दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में जुटे हैं। दरअसल, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रानिक संसाधनों पर अधिक समय बिताना, बाहर का खाना विशेषकर 'जंक फूड' पर निर्भरता, देर रात सोना और सुबह देर से जागना, पारिवारिक अलगाव, एकाकीपन जैसी समस्याएं आज आम हो गई हैं। इन कारणों से तनाव, उच्च रक्तचाप, मोटापा, हृदय की बीमारियां लोगों को घेर रही हैं। अंत में यही कहूंगा कि शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की चुनौती लोगों के साथ-साथ सरकारों की भी जिम्मेदारी है। आज स्वास्थ्य, खेल व शिक्षा के बीच समन्वय की आवश्यकता है।

संसद में हंगामा

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर तीखे प्रहार और प्रतिकार

● **डेस्क**

संसद के दोनों सदनों में हाल ही में जो हंगामा हुआ, वह भारतीय लोकतंत्र के वर्तमान परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण परावर्तन है। राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच हुए करारे वार और पलटवार ने यह स्पष्ट कर दिया कि हमारे राजनीतिक दल किस तरह से अपनी विचारधाराओं और नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। इस सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच हुई जबरदस्त बहस ने इस राजनीतिक टकराव को और भी तीव्र बना दिया।

राष्ट्रपति के अभिभाषण का महत्व

राष्ट्रपति का अभिभाषण, सत्र की शुरूआत में, सरकार की नीतियों और योजनाओं का एक रोडमैप प्रस्तुत करता है। यह देश की दिशा और दृष्टि को स्पष्ट करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के लक्ष्य और प्राथमिकताएं क्या हैं। ऐसे में, जब राष्ट्रपति का अभिभाषण संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो यह समय होता है जब विपक्ष अपनी आलोचनाओं और सुझावों को प्रस्तुत करता है।

विपक्ष का विरोध

इस बार के सत्र में विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। उनकी आलोचनाओं का केंद्र बिंदु विभिन्न नीतिगत फैसलों और योजनाओं की प्रभावशीलता थी। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसकी नीतियां जनविरोधी हैं और वह केवल बड़े उद्योगपतियों के हित में काम कर रही है। विशेष रूप से, आर्थिक नीतियों, कृषि कानूनों और बेरोजगारी के मुद्दों पर विपक्ष ने तीखे सवाल उठाए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के आरोपों का तीखा प्रतिकार किया। उन्होंने कांग्रेस पर करारा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में देश को कई समस्याओं

राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक मुद्दे

राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था। सरकार ने देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों को गिनाया, जिसमें सीमा सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम, और आंतरिक सुरक्षा को बढ़ाने के उपाय शामिल थे।

विपक्ष ने इन मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां आंतरिक सुरक्षा को कमजोर कर रही हैं और देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की कमजोर नीतियों के कारण देश में आतंकी हमलों की घटनाएं बढ़ रही हैं और सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके जवाब में कहा कि उनकी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं और सीमाओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है और सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

में उलझा दिया था और उनकी सरकार उन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, वंशवाद और विकास विरोधी नीतियों का आरोप लगाया।

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार की नीतियां देश के व्यापक विकास और दीर्घकालिक लाभ के लिए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जिनसे गरीबों और पिछड़े वर्गों को लाभ हुआ है। उन्होंने 'आत्मनिर्भर भारत', 'डिजिटल इंडिया', 'मेक इन इंडिया' और 'स्वच्छ भारत अभियान' जैसी योजनाओं का हवाला दिया और कहा कि ये योजनाएं देश को एक नई दिशा देने में सक्षम हैं।

राहुल गांधी का प्रतिकार

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नीतियों पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां केवल बड़े उद्योगपतियों के लाभ के लिए हैं और आम जनता की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। राहुल गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी और कृषि संकट जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और कहा कि सरकार की नीतियां इन समस्याओं का समाधान करने में असफल रही हैं।

राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को लेकर भी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये कानून किसान विरोधी हैं और इससे केवल बड़े उद्योगपतियों को ही लाभ होगा। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने किसानों की मांगों को अनसुना किया और उनके साथ संवाद स्थापित करने में असफल रही। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की नीतियां केवल दिखावे के लिए हैं और जमीनी स्तर पर उनका कोई खास असर नहीं दिख रहा है।

आर्थिक नीतियों पर बहस

इस सत्र में आर्थिक नीतियों पर काफी बहस हुई। विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की हालत को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने सवाल किया कि जब सरकार इतनी योजनाएं चला रही है तो क्यों देश में गरीबों की संख्या बढ़ रही है?

सरकार ने इसके जवाब में कहा कि वैश्विक आर्थिक मंदी और कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डाला है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी योजनाओं का लाभ धीरे-धीरे दिख रहा है और आने वाले समय में स्थिति और बेहतर होगी।

कृषि कानून और किसान आंदोलन

कृषि कानूनों को लेकर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि ये कानून किसान विरोधी हैं और इससे केवल बड़े उद्योगपतियों को ही लाभ होगा। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने किसानों की मांगों को अनसुना किया और उनके साथ संवाद स्थापित करने में असफल रही।

सरकार ने इसके जवाब में कहा कि कृषि कानूनों का उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना और उन्हें ज्यादा स्वतंत्रता देना है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल किसानों को गुमराह कर रहे हैं और उन्हें सच्चाई से दूर रख रहे हैं।

स्वास्थ्य और शिक्षा

राष्ट्रपति के अभिभाषण में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं पर भी प्रकाश डाला गया। सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान उठाए गए कदमों को गिनाया और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए उठाए गए उपायों की जानकारी दी।

विपक्ष ने सरकार की स्वास्थ्य नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार कोविड-19 महामारी से निपटने में असफल रही है और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति दयनीय है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने समय पर उचित कदम नहीं उठाए और देश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं मुहैया कराए।

प्रधानमंत्री मोदी ने इसके जवाब में कहा कि उनकी सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान तेजी से कदम उठाए और देश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक चलाया और देशवासियों को समय पर टीके उपलब्ध कराए।

विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंध

राष्ट्रपति के अभिभाषण में विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी जोर दिया गया। सरकार ने भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और विभिन्न देशों के साथ मजबूत संबंधों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विदेश यात्राओं और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का जिक्र किया।

विपक्ष ने विदेश नीति के क्षेत्र में भी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार की विदेश नीति असफल रही है और भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की प्रतिष्ठा कमजोर हो रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने इसके जवाब में कहा कि उनकी सरकार ने विदेश नीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि मजबूत हो रही है और विभिन्न देशों के साथ संबंध बेहतर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने भारत की विदेश नीति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज को मजबूत किया है।

न्यायपालिका और कानून व्यवस्था

राष्ट्रपति के अभिभाषण में न्यायपालिका और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर भी चर्चा की गई थी। सरकार ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और प्रभावी न्याय प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए।

60 करोड़ भारतीय कर रहे जल संकट का सामना आगे और बढ़ सकती है

● शिल्पा कटौच

दिल्ली जल संकट से बदहाल है। नौबत यहां तक आ पहुंची कि दिल्ली के कई इलाकों कुसुमपुर पहाड़ी, ओखला, संगम विहार, विवेकानंद कैंप आदि में टैंकर के लिए लंबी-लंबी कतारें लग रही है तो वहीं एनडीएमसी ने वीआईपी इलाकों में पानी की आपूर्ति एक बार कर दी है। भारत का आईटी हब कहा जाना वाला बेंगलुरू शहर इन दिनों हर रोज बीस करोड़ लीटर पानी की कमी झेल रहा है। मुंबई और चेन्नई जैसे शहर भी पानी के संकट से जूझ रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इस वक्त करीब 60 करोड़ भारतीय जल संकट का सामना कर रहे हैं। हर साल करीब 2 लाख लोगों की मौत पानी की कमी की वजह से हो रही है। अभी हालात और बिगड़ने की आशंका है क्योंकि 2050 तक पानी की मांग इसकी आपूर्ति से ज्यादा हो जाएगा। डब्ल्यूएमओ की एक रिपोर्ट '2021 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज के अनुसार भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता लगातार घट रही है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता वर्ष 2031 में और घटकर 1,367 क्यूबिक मीटर हो जाएगी। सेंटर फॉर साइंस एंड इंवायरनमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार पानी की बबार्दी का एक अन्य अनुमान बताता है कि हर दिन 4,84,20,000 करोड़ क्यूबिक मीटर यानी 48.42 अरब एक लीटर पानी की बोतलें बर्बाद हो जाती हैं।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार , पिछली शताब्दी में पानी का उपयोग जनसंख्या वृद्धि की दर से दोगुने से भी अधिक बढ़ गया है। 2025 तक, अनुमान है कि 1.8 बिलियन लोग पानी की कमी से ग्रस्त क्षेत्रों में रहेंगे, दुनिया की दो-तिहाई आबादी उपयोग, विकास और जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप पानी की कमी वाले क्षेत्रों में रहती है।

अत्यधिक दोहन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण भूजल संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। भारत की स्थिति इस मामले में चिंताजनक है। भारत में पूरी दुनिया की 17 प्रतिशत आबादी रहती है लेकिन उस अनुपात में जब पानी की बात की जाए तो वह सिर्फ चार प्रतिशत के करीब बैठता है। हैरानी की बात है कि भारत में पूरी दुनिया का सिर्फ चार प्रतिशत शुद्ध जल का स्रोत है।

सेंटर फॉर साइंस एंड इंवायरनमेंट की निदेशक और पर्यावरणविद् सुनीता नारायण कहती है कि इस साल बेंगलुरु में पैदा हुआ जल संकट पूरे देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। हमारे शहर रहने लायक तभी बने रहेंगे जब शहर में रहने वाले गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए भी साफ पेय जल की

सिंगापुर और इजराइल से सीखें भारत के महानगर

भूजल, झीलों और तालाबों को रिचॉर्ज करने के लिए बारिश के पानी का संचय आवश्यक है। इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या कम होगी। सिंगापुर जैसे सबसे आधुनिक शहर वर्षा जल संचयन की प्रैक्टिस करते हैं। सिंगापुर की लगभग आधी भूमि का उपयोग बारिश के पानी को कैप्चर करने के लिए किया जाता है। इस तरह की पहल से बेंगलुरू जैसे शहर पानी की कमी की समस्या को काफी हद तक हल कर सकते हैं। सिंगापुर, इजरायल जैसे देश व विश्व के कई बड़े शहर पानी की बबार्दी रोककर और अपशिष्ट जल को शोधित कर पेयजल संकट को दूर कर रहे हैं। दिल्ली में आधा से अधिक पेयजल चोरी व रिसाव में बर्बाद हो जाता है।

सिंगापुर, टोक्यो सहित अन्य स्थानों पर यह पांच प्रतिशत के आसपास है। दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य आरएस त्यागी का कहना है कि तकनीक के सहयोग से सिंगापुर की तरह दिल्ली में भी पानी वितरण के दौरान व घर में जल की बबार्दी रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। शोधित अपशिष्ट जल का उपयोग कर जल संकट को दूर किया जा सकता है।

उपलब्धता हो। बेंगलुरु में पर्याप्त बारिश होती है, यहां झीलें हैं जो इस बारिश को इकट्ठा कर सकती हैं और भूजल को रिचार्ज कर सकती हैं। इन झीलों के चलते ज्यादा बारिश के समय भी शहर में बाढ़ जैसी स्थिति नहीं बनती है। शहरों में पानी की हर बूंद का इस्तेमाल आने वाले अभाव के दौर के लिए किया जा सकता है। पानी की बचत के लिए शहरों के सीवर में बह जाने वाले पानी के प्रबंधन पर भी विचार करना होगा। इसके लिए जल इंजीनियरों को जमीन पर उतरना होगा, फिर से काम करना होगा और फिर से सोचना होगा। यह आज बेंगलुरु की कहानी है और कल ये किसी भी शहर की कहानी हो सकती है।

सिंगापुर और इजराइल से सीखें भारत के महानगर

भूजल, झीलों और तालाबों को रिचॉर्ज करने के लिए बारिश के पानी का संचय आवश्यक है। इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या कम होगी। सिंगापुर जैसे सबसे आधुनिक शहर वर्षा जल संचयन की प्रैक्टिस करते हैं। सिंगापुर की लगभग आधी भूमि का उपयोग बारिश के पानी को कैप्चर करने के लिए किया जाता है। इस तरह की पहल से बेंगलुरू जैसे शहर पानी की कमी की समस्या को काफी हद तक हल कर सकते हैं। सिंगापुर, इजरायल जैसे देश व विश्व के कई बड़े शहर पानी की बबादी रोककर और अपशिष्ट जल को शोधित कर पेयजल संकट को दूर कर रहे हैं। दिल्ली में आधा से अधिक पेयजल चोरी व रिसाव में बर्बाद हो जाता है।

सिंगापुर, टोक्यो सहित अन्य स्थानों पर यह पांच प्रतिशत के आसपास है। दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य आरएस त्यागी का कहना है कि तकनीक के सहयोग से सिंगापुर की तरह दिल्ली में भी पानी वितरण के दौरान व घर में जल की बबार्दी रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। शोधित अपशिष्ट जल का उपयोग कर जल संकट को दूर किया जा सकता है।

पानी की बबार्दी

औसत भारतीय अपनी दैनिक पानी की जरूरत का 30 प्रतिशत बर्बाद कर देते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक, प्रति मिनट 10 बूंदें टपकने वाला नल प्रतिदिन 3.6 लीटर पानी बर्बाद करता है साथ ही, शौचालय के हर फ्लश में लगभग छह लीटर पानी खर्च होता है। सीएसई की एक रिपोर्ट बताती है कि हर दिन 4,84,20,000 करोड़ क्यूबिक मीटर यानी एक लीटर की 48.42 अरब बोतल पानी बर्बाद हो जाता है, जबकि इस देश में करीब 16 करोड़ लोगों को साफ और ताजा पानी नहीं मिल पाता है।

भारत में पानी की कितनी कमी

वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता लगभग 1,100 क्यूबिक मीटर है, भारी किल्लत को दशार्ता है। जब प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 1,700 क्यूबिक मीटर यानी 17 लाख लीटर से कम होती है, तब माना जाता है कि देश में पानी की कमी हो रही है। लेकिन जब ये उपलब्धता 1,000 क्यूबिक मीटर यानी 10 लाख लीटर से कम हो जाएगी तो माना जाएगा कि भारत में पानी की भयानक किल्लत है। इसकी तुलना में, वैश्विक प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 5,500 क्यूबिक मीटर है।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में अधिकतम जल निकाय बहुत छोटे हैं। भारत के अधिकांश जल निकाय एक हेक्टेयर से भी छोटे हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि कई जल निकायों का पानी इतना पुराना और इतना मैला है कि उसे इस्तेमाल उसे इस्तेमाल करने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं इसलिए इन जल निकायों के पानी को इस्तेमाल करने योग्य भी नहीं बताया गया है।

कृषि पर असर

कृषि में भारत के 80 फीसदी पानी का उपयोग होता है। नीति आयोग की 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक गेहूं की खेती का लगभग 74 फीसदी क्षेत्र और चावल की खेती का 65 फीसदी क्षेत्र 2030 तक पानी की भयंकर कमी का सामना करेगा।

भारत में जल संकट के परिणाम

भारत में जल संकट के कारण कृषि उत्पादकता में कमी, जलजनित बीमारियां और आर्थिक चुनौतियां पैदा होती हैं। इससे विकास में भी बाधा आती है और समुदायों की समग्र खुशहाली पर भी असर पड़ता है।

वेस्ट वाटर का सही इस्तेमाल

काउंसिल ऑन एनर्जी, इनवायरनमेंट एंड वॉटर की 'रीयूज ऑफ ट्रीटेड वेस्टवॉटर इन इंडिया'रिपोर्ट के अनुसार भारत में अगर चुनिंदा

दिल्ली में गिर रहा जलस्तर

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष नवंबर में जारी भूजल रिपोर्ट के अनुसार, राजधानी भूजल स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है। सबसे अधिक खराब स्थिति नई दिल्ली जिले की है अन्य जिलों की स्थिति भी सही नहीं है। दिल्ली की 34 में से सिर्फ तीन में ही भूजल सुरक्षित स्तर पर है, 22 को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है।

कई स्थानों पर यह 20 से 30 मीटर नीचे चला गया है। इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो इन शहरों का भूजल खत्म हो जाएगा। इससे पेयजल संकट और बढ़ेगा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक विश्व के 200 शहर डे जीरो की स्थिति में पहुंच सकते हैं, जिसमें शीर्ष के 10 में भारत के चार शहर दिल्ली, जयपुर, चेन्नई और हैदराबाद शामिल है। डे जीरो का अर्थ है कि शहर में उपलब्ध पानी के सभी स्त्रोत समाप्त हो जाना। इस स्थिति से बचने के लिए भूजल दोहन में कमी लाकर जल संचयन को बढ़ावा देना होगा। पर्यावरणविद् अनिल जोशी कहते हैं कि आज वायु प्रदूषण और बढ़ता जल संसाधन सबसे बड़ी चुनौतियां बन कर हमारे सामने खड़े हैं। शहरों में बढ़ता वायु प्रदूषण अब जानलेवा होने लगा है। ये प्रदूषण कई बीमारियों का भी जनक है। अंधाधुंध दोहन के चलते हमारे जल स्त्रोत सूखते जा रहे हैं। पहाड़ों में बड़ी संख्या में बरसाती नदियां लगभग समापती की कगार पर हैं। भूजल का स्तर भी लगातार नीचे जा रहा है। वहीं जमीन को रीचार्ज करने की कोई व्यवस्था की नहीं जा रही है। ऐसे में समय रहने कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में देश के एक बड़े हिस्से के सामने जल संकट खड़ा होने की स्थिति है। हमें अपने शहरों में घरों या इमारतों के निर्माण के साथ ही अनिवार्य तौर पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए प्रेरित करना होगा। वहीं जल के प्रबंधन के लिए भी कदम उठाने होंगे। जलाशयों की संख्या बढ़ाने के लिए भी कदम उठाने होंगे।

क्षेत्रों में ट्रीटेड वेस्टवॉटर (उपचारित अपशिष्ट जल) को बेचने की व्यवस्था हो तो 2025 में इसका बाजार मूल्य 83 करोड़ रुपये होगा, जो 2050 में बढ़कर 1.9 अरब रुपये पहुंच जाएगा। अध्ययन बताता है कि भारत में पैदा हो रहे वेस्टवॉटर की मात्रा इतनी है कि 2050 तक निकलने वाले वेस्टवॉटर के ट्रीटमेंट से जितना साफ पानी मिलेगा, उससे दिल्ली से 26 गुना बड़े क्षेत्रफल की सिंचाई की जा सकती है।

हर साल कम हो रहा तीन सेंटीमीटर पानी

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) की एक रिपोर्ट '2021 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज' में बताया गया है क भारत में पिछले 20 वर्षों (2002-2021) में स्थलीय जल संग्रहण में 1 सेमी. प्रति वर्ष की दर से गिरावट दर्ज की गई है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता लगातार घट रही है। यह वर्ष 2001 के 1,816 क्यूबिक मीटर की तुलना में वर्ष 2011 में घटकर 1,545 क्यूबिक मीटर हो गई। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता वर्ष 2031 में और घटकर 1,367 क्यूबिक मीटर हो जाएगी।

पानी का लगातार बढ़ रहा उपभोग

विश्व संसाधन संस्थान (डब्ल्यूआरआई) के अनुमानों पर आधारित आंकड़ों से पता चलता है कि विश्लेषण किए गए 164 देशों और क्षेत्रों में से 51 में 2050 तक उच्च से लेकर अत्यधिक उच्च जल तनाव की स्थिति होने की संभावना है, जो कि 31 प्रतिशत आबादी के बराबर है। पूरे अरब प्रायद्वीप, ईरान और भारत के अलावा, अल्जीरिया, मिस्र और लीबिया जैसे अधिकांश उत्तरी अफ्रीकी देश उन देशों में शामिल हैं, जिनके 2050 तक उपलब्ध पानी का कम से कम 80 प्रतिशत उपभोग करने की उम्मीद है।

पानी को लेकर सरकार की योजनाएं

राष्ट्रीय जल नीति- इस नीति के तहत नदी के एक भाग को इस्तेमाल के लिए संरक्षित किए जाने का प्रावधान है तो वहीं नदी के दूसरे भाग को बहते देने का प्रावधान है. जिससे लोगों को पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध हो सके।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को 2015-16 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य खेत पर पानी की भौतिक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था।

जल शक्ति अभियान, 'कैच द रेन' अभियान-सभी स्थितियों के आधार पर जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिये वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण करना।

अटल भूजल योजना-अटल भूजल योजना 6,000 करोड़ रुपये की लागत वाली एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना है। इसमें जल बजट के निर्माण, ग्राम-पंचायत-वार जल सुरक्षा योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन आदि के माध्यम से लोगों की भागीदारी की परिकल्पना की गई है।

दूषित होती नदियां

स्टेट ऑफ एनवायरमेंट (एसओई) 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 30 राज्यों में कुल 279 (46 फीसदी) नदियां प्रदूषित हैं, हालांकि, 2018 के मुकाबले मामूली सुधार 2022 में देखा गया है. 2018 में 31 राज्यों में 323 नदियां प्रदूषित थीं।

जबलपुर की ओमती नदी देखते ही देखते नाले में हुई तब्दील

एक जमाने में कलकल करती बहने वाली ओमती नदी देखते ही देखते नाले में तब्दील हो गई।

खंदारी की किस्मत भी वैसी- जिस तरह ओमती नदी शहरी प्रदूषण का शिकार हुई, ठीक वैसी ही किस्मत खंदारी की भी रही। जानकारों का कहना है कि एक जमाने में बिलहरी, तिलहरी से होते हुए खंदारी नदी ग्वारीघाट से ठीक पहले आकर नर्मदा में मिला करती थी, लेकिन यह भी जल्द नाले में तब्दील हो गई।

उत्तराखंड : देहरादून की रिस्पना को कभी जीवन दायिनी नदी कहा जाता था, जिसका पानी कभी पीने योग्य था, आज उसके अस्तिव पर खतरा मंडरा रहा है।

झारखंड : जमशेदपुर की लाइफ लाइन कही जाने वाली स्वर्णरिखा नदी की नाले से भी बदतर हालत हो गई।

नया कानून...
मगर वह जो अभी होना शेष है

● **अभिषेक कुमार**

देश में तीन ऐतिहासिक कानूनी परिवर्तन किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ऐसे ही परिवर्तन हैं। उम्मीद है ये औपनिवेशिक अवशेषों को भी खत्म कर देंगे। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी, 1860) और इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 ब्रिटिश राज की कानूनी व्यवस्थाएं थीं, जिन्हें हम आज भी ढो रहे थे। ये 'उपनिवेश की गुलामी' की याद दिलाती थीं। अब उनके स्थान पर पूर्णतः भारतीय संहिताएं होंगी। आपराधिक प्रक्रिया संहिता भी 1898 की विधिक व्यवस्था थी, लेकिन अब 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' ने उसका स्थान लिया है। वस्तुतः ये कानून राज्य के साथ नागरिक के संबंधों और समझौतों को परिभाषित करते थे। कानून का राज स्थापित करने के मद्देनजर बलपूर्वक भी व्यवस्था कार्रवाई करती थी। अर्थात कानूनों का दुरुपयोग होता था। खासकर हमारे आपराधिक न्याय को लेकर कई सवाल और ढेरों आपत्तियां की जाती रही हैं। कानून और दृष्टि अप्रासंगिक हो चुके थे। जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या असीमित हो गई है। पीड़ित पक्ष को इंसाफ के लिए जिंदगी भर जूतियां घिसनी पड़ती हैं, तब भी इंसाफ की उम्मीद अधूरी है। अदालतों में करोड़ों मामलों की भरमार है। यह बोझ बढ़ता जा रहा है। सब कुछ अनिश्चित और अपरिमित है, लिहाजा इन व्यवस्थाओं में सुधार की गुंजाइश लंबे अंतराल से महसूस की जा रही थी। इन तीनों नए कानूनों पर संसद की स्थायी समितियों में विमर्श किया गया होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जुलाई, 2020 में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी। उसने देश के नागरिकों के लिए एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की थी और उसे जारी भी किया गया। उस सूची में आपराधिक वैवाहिक बलात्कार, यौन अपराधों को लैंगिक तौर पर निरपेक्ष बनाना, इच्छा-मृत्यु और राजद्रोह सरीखे अपराधों पर नागरिकों के अभिमत लिए जाने थे।

अभिमत कितनी संख्या में आए, कितने राज्यों के किन-किन वर्गों के लोगों ने अपने अभिमत दिए, भारत सरकार ने उनका कोई खुलासा नहीं किया है। दरअसल संसद में ये विधेयक तब पारित किए गए, जब 146 सांसद निलंबित थे और सदनों में एकतरफा बहुमत था, लिहाजा ध्वनि-मत से विधेयक पारित किए गए। बाद में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से वे कानून बन गए, लेकिन इस संदर्भ में अब भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। इन तीनों संहिताओं और अधिनियम पर देश का जनमत सामने आना भी शेष है, क्योंकि एक जुलाई से ही ये ऐतिहासिक परिवर्तन लागू किए गए हैं।

अब 'प्राथमिकी' का नामकरण तक बदल दिया गया है। सजा के वैकल्पिक स्वरूप के तौर पर सामुदायिक सेवा का प्रावधान भी किया गया है। छोटे अपराधों के लिए 'समरी ट्रायल' को अनिवार्य किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ट्रायल अब सुनिश्चित होगा। भीड़-हत्या और हिंसा, बाल विवाह बलात्कार ऐसे अपराध हैं, जिनका समयबद्ध और गतिमय ट्रायल अनिवार्य होगा। अधिकतर सलाह-मशविरा, विमर्श कोरोना महामारी के दौरान किए गए, लिहाजा संहिताओं में कुछ बड़े परिवर्तन नहीं जोड़ पाए होंगे।

कुछ राज्यों ने भी आपत्तियां की हैं और मांगें भी की हैं। मसलन-कानूनों के नाम अंग्रेजी में नहीं होने चाहिए। क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने में काफी वक्त लगता है। कर्नाटक सरकार ने आपत्ति की है कि प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्राथमिक जांच के लिए पुलिस अफसर को 14 दिन का वक्त क्यों दिया जाना चाहिए? धारा 377 को बिल्कुल हटा देने पर भी सवाल किए गए हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि अंतरिम जमानत के प्रावधानों में कुछ अपवाद रखे जाएं और इस पर एक अध्यादेश लाया जाए।

बहरहाल कुछ राज्यों के आग्रह तार्किक हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। इन कानूनों की अभी समीक्षा की जानी चाहिए। नई लोकसभा में जो स्थायी समितियां बनेंगी, उनके सांसद-सदस्यों को पुनरावलोकन के लिए ये संहिताएं दी जाएं। इनसे जुड़े जहां भी कन्फ्यूजन हैं उन्हें दूर किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी जिन्हें केंद्र सरकार का विरोध ही करना है, वह नए सिरे से इन कानूनों को आधार बनाकर विरोध करते दिखते हैं। देश की समाजिक एवं कानून व्यवस्था के नजरिए से यह ठीक स्थिति नहीं है। ऐसे में अभी इस दिशा में बहुत जनजागृति किए जाने की आवश्यकता भी महसूस होती है।

सार्थक संवाद की दृष्टि से निराशाजनक रहा लोकसभा का पहला सत्र

● **रामावतार सिंह**

भारतीय संसद अपनी गौरवशाली परंपराओं, विमर्शों और संवाद के लिए जानी जाती है। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकतांत्रिक बहसों को प्रोत्साहित किया और अपने प्रतिपक्ष के नेताओं डॉ.राममनोहर लोहिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, फिरोज गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर पीलू मोदी तक को मुग्ध भाव से सुना। राष्ट्रप्रेम ऐसा कि चीन युद्ध के बाद गणतंत्र दिवस की परेड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को आमंत्रित कर उनकी राष्ट्रभक्ति को सराहा। किंतु लोकसभा के प्रथम सत्र में जो कुछ हुआ,वह संवाद की धारा को रोकने वाला है। इससे संसद विमर्श और संवाद का केंद्र नहीं अखाड़ा बन गई।

राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में जब नेता सदन और प्रधानमंत्री बोल रहे थे, उनके लगभग दो घंटे के भाषण में विपक्षी सदस्यों ने आसमान सिर पर उठा रखा था। लगातार नारेबाजी से उनका भाषण सुनना मुश्किल रहा। इसके विपरीत जब पहले दिन नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, तो उनके भाषण में सत्तारूढ़ दल के प्रधानमंत्री सहित तीन मंत्रियों ने हस्तक्षेप किया। नेता प्रतिपक्ष को बताया गया कि वे सदन के पटल पर गलत तथ्य न रखें। यह दोनों स्थितियां भारतीय राजनीति में बढ़ते अतिवाद को स्पष्ट करती हैं, जहां संवाद संभव नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष पर नेता प्रतिपक्ष द्वारा की गई अनावश्यक टीका-टिप्पणी को भी इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष की गलतबयानी के लिए बाद में सत्तारूढ़ दल के वक्ता अपने भाषणों में उनके भाषण की चीरफाड़ कर सकते थे। किंतु शीर्ष स्तर से लगातार हस्तक्षेप ने नेता प्रतिपक्ष का मनोबल बढ़ा दिया। वे सत्ता पक्ष को उत्तेजित करने में सफल रहे और पहले दिन के मीडिया विमर्श में उन्हें 'सक्रिय नेता प्रतिपक्ष' घोषित कर दिया गया। सेकुलर मीडिया के सेनानियों ने उन्हें 'मैन ऑफ द मैच' घोषित कर दिया। जाहिर है लंबे समय से गंभीर राजनेता की छवि बनाने के लिए आतुर राहुल गांधी के लिए यह अप्रतिम समय था। किंतु पहले दिन की वाहवाही अगले दिन ही धराशाई हो गई जब प्रधानमंत्री के भाषण में दो घंटे तक नारेबाजी चलती रही। देश की जनता दोनों तरह की अतियों के विरुद्ध है। सदन की गरिमा को बचाने के लिए राजनीतिक दलों को कुछ ज्यादा उदार होना चाहिए।

> हमारे संसदीय परंपरा का मूलमंत्र है संवाद से संकटों और समस्याओं का समाधान खोजना। संसद इसी का सर्वोच्च मंच है। यह प्रक्रिया नीचे पंचायत तक जाती है। इससे सहभागिता सुनिश्चित होती है, सुशासन का मार्ग प्रशस्त होता है।

लोकसभा के प्रथम सत्र से निकली छवियां बता रही हैं कि आगे भी सब कुछ सामान्य नहीं रहने वाला है। किंतु संसद को अखाड़ा, चौराहे की चर्चा के स्तर पर ले जाने के लिए किसे जिम्मेदार माना जाए? यह ठीक बात है कि सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, किंतु सदन में सार्थक और प्रभावी विमर्श खड़ा करना विपक्षी दलों की भी जिम्मेदारी है। अब जबकि विपक्ष अपनी बढ़ी संख्या पर मुग्ध है तो क्या उसे संसदीय मर्यादाओं को छोड़कर अराजकता का आचरण करना चाहिए? सच तो यह है कि सदन के इस तरह चलने से सत्तारूढ़ दल का ही लाभ है।

बिना बहस और चर्चा के कानून इसीलिए पास होते हैं क्योंकि संसद का ज्यादातर समय हम विवादों में खर्च कर देते हैं। संसदीय परंपरा रही है कि हर नई सरकार को प्रतिपक्ष कम से कम छह माह का समय देता है। उसके कार्यक्रम और योजनाएं का मूल्यांकन करता है। पहले दिन से ही सदन को अराजकता की ओर ढकेलना उचित नहीं कहा जा सकता। अपनी लंबी संसदीय प्रणाली में भारत ने अनेक संकटों का समाधान किया है। हमारे संसदीय परंपरा का मूलमंत्र है संवाद से संकटों और समस्याओं का समाधान खोजना। संसद इसी का सर्वोच्च मंच है। यह प्रक्रिया नीचे पंचायत तक जाती है। इससे सहभागिता सुनिश्चित होती है, सुशासन का मार्ग प्रशस्त होता है। संसद से नीचे के सदनों विधानसभा सभाओं,विधान परिषदों, नगरपालिका, नगर निगमों और पंचायतों को भी सांसदों का आचरण ही रास्ता दिखाता है।

लोकसभा के पहले सत्र का लाइव प्रसारण देखते हुए हर संवेदनशील भारतीय जन को ये दृश्य अच्छे नहीं लगे हैं। संसदीय मर्यादा और परंपरा की रक्षा हमारे सांसद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? संसदीय राजनीति के शिखर पर बैठे दायित्ववान सांसदों की यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वे अपने आचरण से इस महान संस्था का गौरव बढ़ाने में सहयोगी बनें। नफरत, कड़वाहट और संवादहीनता से हम 'राजनीति' में सफल हो सकते हैं किंतु 'राष्ट्रनीति' में विफल हो जाएंगे।

लोकसभा चुनाव और अयोध्या

● **संतोष कुमार सिंह**

भाजपा ने अयोध्या को उसके शाब्दिक अर्थ के रुप में ही स्वयं के लिए भी अपराजेय मान लिया था मगर सारे किये धरे पर पानी फिर गया। भव्य मंदिर निर्माण के साथ ही श्रीराम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का जो अभूतपूर्व वातावरण सृजित कर हिन्दुत्व की हुंकार भरी गयी, वह जातीय समीकरण के आगे मद्धिम पड़ गयी। भारत ही नहीं, सारे विश्व के हिन्दुओं में अयोध्या पराजय की थू थू हुई। बहुत से श्रद्धालुओं का अयोध्या जाने का उत्साह ही टूट गया। काश अयोध्या के लिये एक सजग रणनीति बनाई गयी होती। इस खामखयाली और बेपरवाही में आखिर भाजपा कैडर क्यों डूबा रहा कि वहां तो श्रीराम जी बेड़ा पार करा ही देंगे जबकि दूसरी ओर जातीय समीकरण साधने की चतुर रणनीति बनी और कारगर हो गयी। इससे सबक क्या मिला? यही न कि जातियों में बंटे भारत में एक बड़ी जनसंख्या ऐसे लोगों की भी है जिनके लिये हिन्दुत्व, मंदिर, महादेव, श्रीराम और कृष्ण कोई मायने नहीं रखते। उनके लिये जाति पांत सर्वोपरि है।

ऐसे ही हिन्दू हजार वर्ष गुलाम नहीं रहा। इतिहास साक्षी है कि कैसे कुछ जातियां बिना तनिक भी प्रतिरोध के इस्लामी आतंक के आगे नतमस्तक हो गयीं थी। उन्हें तब भी अपने हिन्दू स्वाभिमान का भान नहीं था और आज भी उन्हें आसन्न इस्लामी खतरों का अहसास तक नहीं है। उन्हें बस जाति के नाम पर आसानी से बरगलाया जा सकता है और अयोध्या में वही हुआ जिसका तनिक भी पूवाभास भाजपा को नहीं था। जोर का धक्का जोर से ही लगा। देश और विश्वभर के हिन्दुत्व प्रेमियों का जो उच्चाटन हुआ वह अलग। आज सभी ठगे से महसूस कर रहे हैं।

कई विचारकों का मानना यह भी है कि देव स्थानों के तेजी से पर्यटन स्थल के रूप में व्यवसायीकरण से उनकी मूल प्रकृति विकृत या दूषित हो रही है जिसके प्रति अयोध्या की जनता ने अपना रोष प्रगट कर दिया है मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। मानव जीवन के बदलते मूल्यों और आधुनिकता के लिहाज से देवालयों को भव्य रुप देना और उसके इको सिस्टम को समृद्ध बनाना सर्वथा उचित है। इससे व्यवसाय, रोजगार और स्थिर आजीविका के नयी संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। यह भला कहां से अनुचित है?

देवालयों के पुनरुद्धार के पहले उनमें पसरी गंदगी, घूमते आवारा पशु और रास्ते में पड़े मल मूत्र गोबर के दृश्यों को क्या हम भूल पाये हैं? ऐसे में पूजा पाठ का भाव क्या तिरोहित नहीं हो जाता था? काशी की तो एक कहावत मन में कैसी जुगुप्सा ला देती थी - राड़ साड़ सीढ़ी सन्यासी इनसे बचें तो सेवें काशी। अब आज की काशी की यह पहचान नहीं रही। वह चमक दमक रही है। हलांकि इसका भी जातीय मकड़जाल में फंसे मतदाताओं पर कोई असर नहीं हुआ।

मतगणना में मोदी जी के आरंभिक दस चरणों में पीछे बने रहना खेदजनक प्रमाण है हालाँकि वाराणसी कैंट जहां महादेव स्वयं हैं, ने लाज रख ली। ठीक वैसे ही अयोध्या कैंट ने भाजपा की लाज तो रखी मगर अन्य विधानसभाओं में हुये नुकसान की भरपाई नहीं हो सकी। यह जो अनर्गल बात फैलायी जा रही है कि अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं को वहां के दुकानदारों से खरीद फरोख्त न करके उनकी कृतघ्नता का मजा चखाना चाहिये, बिल्कुल अनुचित है। अयोध्या खास से तो भाजपा की लाज बच गयी। नुकसान दूसरी विधानसभाओं से हैं जहां दलितों के एक बड़े वर्ग ने भाजपा का साथ छोड़ दिया।

हलांकि अब श्रीराम मंदिर के दर्शन का उत्साह निश्चय ही फीका पड़ गया है मगर इस अनचाहे बहिष्कार से तो हिन्दुत्व विरोधी ताकतों को ही बल मिलेगा और वे और संगठित होंगी। वे जिन्हें मंदिर और हिन्दुत्व से कुछ लेना देना नहीं और जिनके लिये जाति ही सर्वोपरि है, ऐसे लोगों को को माकूल जवाब तो निरंतर श्रीराम धाम में जाकर मत्था टेकने और खूब खरीदारी करने से ही मिलेगा। तभी उनके नापाक हौसले पस्त होंगे। इसलिए मैं स्वयं शीघ्र ही सपरिवार स्वजन सहित अयोध्या गमन का कार्यक्रम बना रहा हूं। आप कब पहुंच रहे हैं अयोध्या?

यूपी विस उप चुनाव के लिये बीजेपी तैयार कर रही है नया रोडमैप

● अजय कुमार

उत्तर प्रदेश में दस विधान सभा सीटों के उप-चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और योगी सरकार वह सब खामियां दूर कर लेना चाहते हैं जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में पार्टी और मोदी-योगी की काफी किरकिरी हुई थी। लोकसभा चुनाव में यूपी में सीटें कम होने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष गत दिवस 05 जुलाई लखनऊ पधार चुके हैं। संतोष लोकसभा चुनावों में सीटें कम होने के बाद पहली बार यूपी आये हैं। वह अपने दौरे में न केवल सरकार और संगठन के काम की थाह ले रहे है बल्कि लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी की हार हुई है, उनकी समीक्षा भी कर रहे हैं। वह संगठन के पदाधिकारियों के साथ सरकार के मंत्रियों के साथ भी बात करेंगे।

गौरतलब हो,बीजेपी आलाकमान लोकसभा में यूपी से मात्र 33 सीटें आने के बाद सभी लोकसभा सीटों पर स्पेशल टीम भेजकर अपनी रिपोर्ट तैयार करा चुकी है। यह रिपोर्ट केंद्रीय मुख्यालय को भेजी भी जा चुकी है। इस रिपोर्ट के केंद्रीय मुख्यालय पर पहुंचने के बाद राष्ट्रीय स्तर का कोई पदाधिकारी पहली बार भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर आया है। बीएल संतोष आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पार्टी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान उनके द्वारा हारी हुई सीटों और 8.5 फीसदी वोट शेयर कम होने को लेकर एक-एक सीट की पड़ताल की जा रही है। इस पर बात करने के लिए क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ क्षेत्रीय प्रभारियों और प्रदेश पदाधिकारियों को बुलाया गया है। संतोष सरकार के मंत्रियों से भी बात करेंगे। यूपी सरकार में शामिल 16 मंत्री अपना ही क्षेत्र नहीं जिता सके थे। इसकी भी रिपोर्ट केंद्रीय मुख्यालय को भेजी गई है।

सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की इस बैठक में रिपोर्ट में आए नतीजों के हिसाब से सरकार और संगठन में बदलाव पर भी मंथन होगा। वह सरकार के कामकाज भी भी समीक्षा करेंगे। सूत्रों के अनुसार जितिन प्रसाद के मंत्री और अनूप वाल्मीकि के सांसद बन जाने के बाद सरकार में दो मंत्री बनाए जा सकते हैं। कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। इसके अलावा कई जिलों से संगठन के भी सहयोग न करने की जानकारी सामने आयी है। कुछ जिलों में भितरघात की भी शिकायतें सामने आयी हैं। इस वजह से उनमें भी बदलाव किया जा सकता है।

संतोष के साथ बैठक करके बीजेपी के बड़े नेता 14 जुलाई को पहली बार लखनऊ में होने के जा रही विस्तारित प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की भी रूपरेखा भी बनायेंगे। इस कार्यसमिति की बैठक में पहली बार बीजेपी के संगठन की दृष्टि से बने 1918 मंडलों के मंडल अध्यक्ष बुलाए गए हैं। कार्यसमिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। समिति में किन विषयों पर चर्चा होगी, कितने सत्र रहेंगे? इसकी पूरी रूपरेखा बनेगी। लोकसभा चुनाव में दलितों-पिछड़ों के वोट क्यों कम मिले? कैसे उसे फिर से अपना बनाया जा सकता है। कैसे बीजेपी मिशन 2027 पर काम करे, इसका रोड मैप तय होगा,इसके साथ ही रोड मैप का विधान सभा उप चुनाव में लाइव टेस्ट भी हो जायेगा।

भू-माफियाओं और दबंगों के खिलाफ योगी ने फिर दिखाए सख्त तेवर

● **अजय कुमार**

सरकारी और निजी जमीनों पर भू माफियाओं और दबंगों की हमेशा नजर रहती है। वह इसे हथिया कर ऊंचे दामों पर उन लोगों को बेच देते हैं जिनको यह नहीं पता होता है कि जमीन की वैधानिक स्थिति क्या है। परिणाम स्वरूप कई बार भूमाफियों के चंगुल में फंस कर लोग अपनी उम्र भर की कमाई लुटा बैठते हैं। इसी से चिंतित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफिया और कमजोरों को उजाड़ने वाले दबंग किसी भी दशा में बख्शे न जाएं। उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का अनुसरण करते हुए कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सरकार का संकल्प है कि किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जमीन कब्जा करने के मामलों में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान करीब 400 लोगों से मुलाकात कर उन्होंने सबको आश्वस्त किया कि उनके रहते किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। उन्होंने सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश देने के साथ लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सबको न्याय मिलेगा और सबकी पीड़ा दूर की जाएगी। जनता दर्शन में दूसरे जिलों के भी लोग आए थे। सीएम से मिलकर समस्या बताने वालों में महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा काफी अधिक रही। जनता दर्शन में कुछ महिलाओं ने भूमाफिया और दबंगों द्वारा जमीन कब्जा करने की शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमाफिया को करारा सबक सिखाया जाएगा। उनके रहते कोई भी किसी कमजोर या गरीब को उजाड़ नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद प्रशासन व पुलिस के अफसरों को निर्देशित किया कि जबरन जमीन कब्जा करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई करें। सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी दबंग, माफिया, अपराधी किसी की जमीन पर कब्जा न करने पाए।

मुख्यमंत्री के समक्ष जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। सीएम योगी ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार इलाज के लिए भरपूर मदद करेगी। उनके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को सौपते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इलाज से जुड़ी इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करा कर शासन में उपलब्ध कराया जाए।

सीएम ने अफसरों से कहा कि वे हर जरूरतमंद का आयुष्मान कार्ड बनवाएं ताकि इलाज के लिए उन्हें परेशान न होना पड़े। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को दो टूक हिदायत देते हुए कहा कि जनसमस्याओं के निस्तारण में हीलाहवाली अक्षम्य होगी। हर व्यक्ति की समस्या का पूरी प्रतिबद्धता और पारदर्शिता से न्यायोचित समाधान शासन-प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारी पूरी संवेदनशीलता से लोगों की समस्याओं को सुनें और गुणवत्तापूर्ण, त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। इस दौरान पुलिस व राजस्व से जुड़ी शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी जिले स्तर पर ही समस्या का समाधान सुनिश्चित करें ताकि लोगों को परेशान न होना पड़े। कड़े तेवर में उन्होंने कहा कि संवेदनहीन और लापरवाह अधिकारियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

प्रदूषण का प्रहार झेलती महिलाएं

● **विजय गर्ग**

भारत में वायु प्रदूषण से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक विश्व की लगभग पूरी आबादी ऐसी हवा सांस रही है, जिसमें प्रदूषक तत्त्व तय दिशा-निर्देशों की सीमा से कहीं अधिक है। 2019 में इसकी वजह से करीब 67 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। यो प्रदूषण सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन बुजुर्गों की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण उन पर और अधेड़ उम्र की महिलाओं के स्वास्थ्य पर यह घातक असर डाल रहा है। बुजुर्ग महिलाएं अपना अधिकांश समय घरों के भीतर व्यतीत करती हैं। मगर वे घर के भीतर भी वायु प्रदूषण से जूझ रही हैं। प्रदूषण के कारण उनमें नेत्र, त्वचा, नाक, गले में खुजली, चक्कर आना, थकान, रक्तचाप, चिड़चिड़ापन, अवसाद, अनिद्रा, बहरापन, मानसिक रोग, पेट संबंधी रोगों में लगातार इजाफा हो रहा है। हाल में हुए शोध बताते हैं कि वायु प्रदूषण से कुछ गंभीर रोग भी तेजी से बढ़े हैं, जो बुजुर्ग महिलाओं को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं।

चिकित्सक मानते हैं कि वायु प्रदूषण से फेफड़े और दिल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। अध्ययन बताते हैं कि भारत में हर एक हजार में से बीस बुजुर्ग वायु प्रदूषण से मनोभ्रंश के शिकार हुए हैं। बुजुर्ग महिलाओं में इसका प्रसार अधिक बताया गया है। 'इंपीरियल' के पर्यावरण अनुसंधान समूह के प्रमुख और लेखक, प्रोफेसर फ्रैंक केली मुताबिक इक्कीसवीं सदी में स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल के लिए डिमेंशिया बड़ी चुनौतियों में से एक है। येल और पेकिंग विश्वविद्यालय में संयुक्त रूप से हुए एक अध्ययन के मुताबि वायु प्रदूषण के कारण मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। इसमें सबसे ज्यादा बुजुर्गों के मस्तिष्क को हानि पहुंचती है। अध्ययन के मुख्य आर्थर जियाबो गैंग का कहना है कि वायु प्रदूषण के कारण लोगों की बोलने की क्षमता ज्यादा प्रभावित होती है। दिमाग पर वायु प्रदूषण का इतना बुरा असर होता है कि बहुत से लोग बोलने के लिए शब्द तक मुंह से नहीं निकाल पाते हैं। इस अध्ययन कहा गया है कि अगर कोई इंसान लंबे समय तक वायु प्रदूषण की चपेट में रहता है, तो उसकी अनुभूति की क्षमता ज्यादा प्रभावित होती है।

जब कभी वायु प्रदूषण की बात उठती है तो घरेलू वायु प्रदूषण को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, जबकि घरेलू वायु प्रदूषण कई तरह की जानलेवा बीमारियों की वजह है अंदरूनी हवा उतनी ही विषैली होती है, जितनी कि बाहरी शहरी परिवेश के साथ ग्रामीण परिवेश में भी घरों में मौजूद वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। 'जर्नल बीएमसी' में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, जो महिलाएं अपने घरों में वायु प्रदूषण के संपर्क में हैं, उनमें याददाश्त, रोजमर्रा के कामों को करने की क्षमता, तार्किक और बौद्धिक क्षमता अन्य महिलाओं की तुलना में कम है। आज भी विकासशील देशों में अधिकांश ग्रामीण घरों में खाना पकाने के लिए दुनिया की करीब एक तिहाई आबादी मिट्टी का तेल, लकड़ी, फसलों के अवशेषों, गोबर और कोयला आदि इस्तेमाल करती है, जो कि घरों में हानिकारक वायु प्रदूषण का कारण बनता है। ग्रामीण परिवेश में किए शोध और आंकड़े बताते हैं कि यह खतरा बुजुर्ग और अधेड़ महिलाओं के लिए ज्यादा खतरनाक है। कोयले के संपर्क में रहने वाली महिलाओं में फेफड़ों के कैंसर का जोखिम दोगुना होता है।

मेडिकल जर्नल 'ट्रांसलेशनल साइकेट्री' द्वारा 2017 में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया है कि वृद्ध महिलाएं, जो उच्च स्तर के बारीक कण वाले पदार्थ सहित प्रदूषित क्षेत्रों में रहती हैं, वे तेजी से उम्र बढ़ने और दिमाग की कमजोरी का अनुभव करती हैं। उनमें मनोभ्रंश और अल्झाइमर जैसी बीमारियों के लक्षण देखने को मिले। स्पेन के बार्सिलोना में यूरोपियन रेस्पिरेटरी सोसाइटी

इंटरनेशनल कांग्रेस' में प्रस्तुत किए गए नए अध्ययन से पता चला है कि महिलाओं के लिए डीजल के धुएं में सांस लेना जानलेवा हो सकता है। शोधकर्ताओं ने डीजल निकास' के संपर्क में आने से लोगों के खून में बदलाव की बात कही है। इससे महिलाओं में सूजन, संक्रमण और हृदय रोग से संबंधित रक्त के घटकों में परिवर्तन पाए गए हैं। शोध के मुताबिक फेफड़ों के कैंसर के लगभग दस में से एक मामले के लिए बाहरी वायु प्रदूषण एक कारण हो सकता । वायु प्रदूषण के कण कोशिकाओं में डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं। कैंसर का जोखिम हो सकता है।

इससे हार्वर्ड टीएच के नेतृत्व में एक अध्ययन में पाया गया कि लंबे समय तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने से बुजुर्गों में अवसाद का खतरा बढ़ सकता है। सिर्फ पांच दिनों तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने से बुजुर्ग महिलाओं में आघात का खतरा बढ़ सकता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 'मेलमैन स्कूल आफ पब्लिक हेल्थ' के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में किए एक नए अध्ययन से पता चला है कि वातावरण में बढ़ता वायु प्रदूषण महिलाओं की हड्डियों के लिए भी खतरनाक है। अध्ययन के अनुसार बढ़ती उम्र में वायु प्रदूषण का संपर्क महिलाओं में 'बोन मिनरल डेंसिटी' में कमी के साथ ऑस्टियोपोरोसिस से भी जुड़ा है। इसकी वजह से हड्डियों के टूटने का जोखिम बढ़ जाता है। इससे पहले भी शोध इस बात के सबूत सामने आए थे कि वायु प्रदूषण महिलाओं की हड्डियों के लिए खतरनाक हो सकता है। 1990 से 2019 के बीच कम होती 'बोन मिनरल डेंसिटी' और उनमें टूटन के कारण विकलांगता में 121 फीसद की वृद्धि हुई है। यह शोध बताते हैं कि वायु प्रदूषण के सूक्ष्म कणों के संपर्क में लंबे समय तक रहने से रजोनिवृत्ति के बाद की महिला में हृदय संबंधी रोग के जोखिम और मृत्यु की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने भी पाया कि स्तन कैंसर की घटनाओं में सबसे अधिक वृद्धि उन महिलाओं में पाई गई, जिनका संपर्क 'पार्टिकुलेट मैटर' स्तर पीएम 2.5 से अधिक था। मोटर वाहन से निकलने वाले धुंए, तेल कोयला जलाने या लकड़ी के धुंए आदि में पीएम 2.5 अधिक होता है। बुजुर्ग महिलाएं पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होती हैं। उन्हें उन खतरों के बारे होना चाहिए कि उनकी हवा कितनी खराब हो सकती है। इसे कम करने और इससे खुद को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है।

वे जहां रहती हैं, वहां वायु की गुणवत्ता की दैनिक आधार पर निगरानी करें। जहां प्रदूषण अधिक है, वहां न जाएं। औद्योगिक प्रदूषण वाली जगहों से और रोशनी के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का उपयोग करें रसोई का क्षेत्र अच्छी तरह हवादार हो ।स्टोव, चिमनी और अन्य उपकरणों का रखरखाव करें, ताकि वे कुशलतापूर्वक ईंधन जला सकें। भवन और पेंट उत्पाद, सफाई और घरेलू रसायनों सहित इनडोर प्रदूषकों के अन्य सामान स्रोतों से सावधान रहें। हमारे बुजुर्ग जितने स्वस्थ होंगे, वायु प्रदूषण के संपर्क के बाद स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं उत्पन्न होने की संभावना उतनी ही कम होंगी।

बचपन को प्रबुद्ध करो, यौवन को शुद्ध करो, बुढ़ापे को सिद्ध करो

● आशिमा 'राज' वार्ष्णेय

मनुष्य जीवन की तीन अवस्थाएं हैं बाल्यावस्था, युवावस्था एवं वृद्धावस्था। तीनों ही अवस्थाओं में हम सतत कुछ न कुछ सीखते हैं। परंतु बाल्यावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बचपन में सीखने की क्षमता सबसे होती है, जो उम्र बढ़ने के साथ-साथ शनैः शनैः कम होती जाती है। बचपन में जितनी अधिक शिक्षा प्राप्त कर सकें, जो कुछ सीख सकें सीखना चाहिए। चाहे वह भाषा हो, नृत्य, संगीत या वाद्य यंत्र। सभी को सीखने में सबसे कम समय लगता है।

बालक जिज्ञासु होते हैं। उनकी जिज्ञासा यथासंभव शांत करनी चाहिए। उनके प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए न कि डांट डपट कर चुप कराया जाए। अल्बर्ट आइंस्टीन का कथन है ्रयदि आप बच्चों को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें परियों की कहानियां सुनाएं, यदि आप उन्हें और भी अधिक बुद्धिमान जा बनाना चाहते हैं तो उन्हें और अधिक परियों की कहानियां सुनाएं।्र

माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बालक के बचपन को प्रबुद्ध बनाने के लिए भरसक प्रयास करें। उन्हें अच्छे संस्कार दें, प्रेरणादायक कहानियां सुनाएं, जिससे उनमें संस्कार सिंचन हो। आजकल के कुछ कार्टून जिनमें एक दूसरे पर प्रहार किया जाता है उनसे बच्चों को दूर रखना चाहिए। बालक का सर्वांगीण विकास ही उसे एक अच्छा नागरिक बनने में सहयोगी होगा।

युवावस्था तक आते-आते कुछ बच्चों के खानपान और सोने आदि की आदतों में परिवर्तन आ जाता है। यह माता-पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों पर ध्यान दें जिससे उनमें गलत आदतें ना पड़ें। बचपन में दिए गए संस्कार ही युवावस्था में काम आते हैं। युवा हमारे भविष्य की उम्मीद हैं। युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की अनमोल संपत्ति होती है। इस अवस्था में जोश चरम सीमा पर होता है। कुछ कर गुजरने की चाहत होती है।

चाणक्य के अनुसार ्रशिक्षा सबसे अच्छी दोस्त है एक शिक्षित व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है।्र शिक्षित युवा अपनी बुद्धि के बल पर अपने देश की प्रगति में भागीदार होता है। कमजोर युवा जो बुरी लतों के अधीन हो जाते हैं वे अपने परिवार के दुख का कारण होते हैं। अरस्तु का कथन है ्रयुवावस्था में डाली गई अच्छी आदतें सारा अंतर ला देती हैं।्र अतः युवावस्था में शारीरिक एवं मानसिक शुद्धता का होना अति आवश्यक है। कर्तव्यनिष्ठ एवं अनुशासित युवा देश की तस्वीर बदल सकते हैं।

वृद्धावस्था जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव है। कुछ लोग सोचते हैं कि बूढ़ा व्यक्ति बेकार होता है, परंतु वृद्धों के पास अनुभव का खजाना होता है जो जीवन जीने की राह दिखाता है। उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बहेलिए और कबूतर की कहानी तो सभी ने सुनी ही है। बूढ़े कबूतर की मदद से ही समस्त कबूतर जाल से आजाद हो पाए थे।

इंसान को जब तक अपने काम और शरीर का सहयोग मिल रहा है तब तक वह वृद्ध नहीं होता, चाहे उसकी उम्र कुछ भी क्यों ना हो। आयु बढ़ने पर भी अपने भीतर उत्साह बनाए रखना चिर यौवन को आमंत्रण देता है। मन की ताकत का शरीर पर बहुत असर होता है। वृद्धावस्था में सकारात्मक विचार रखने से ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक सोच से शरीर की ऊर्जा क्षीण होती जाती है। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अतः अपने शरीर को स्वस्थ रख एवं सकारात्मक रहकर वृद्धावस्था का आनंद लेना चाहिए।

जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी का कथन ्रबचपन को प्रबुद्ध करो, यौवन को शुद्ध करो, बुढ़ापे को सिद्ध करो्र प्रेरणादायक है साथ ही साथ जीवन जीने की कला सिखाता है।

भ्रष्टाचार का विकास

पुल और अन्य निर्माणों की गुणवत्ता पर सवाल

● अंकित श्रीवास्तव

भारत में अवसंरचना विकास के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हो रही है। सड़कों, पुलों, भवनों और अन्य सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं पर भारी निवेश किया जा रहा है। सरकारें दावा करती हैं कि यह विकास लोगों की सुविधाओं को बढ़ाने और आर्थिक प्रगति को तेज करने के लिए है। लेकिन इन दावों के बावजूद, कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो विकास कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाती हैं। पुलों के गिरने और अन्य निर्माण परियोजनाओं की विफलता के उदाहरण भ्रष्टाचार और लापरवाही की ओर इशारा करते हैं। क्या भ्रष्टाचार का भी विकास हो रहा है?

बिहार में बीते कई दिनों में एक के बाद एक पुल गिरे हैं। आम जनता के लिए यह जानना जरूरी है कि इन पुलों के निर्माण में किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। सरकार निर्माण कार्यों की निगरानी क्यों नहीं करती। सवाल यह भी उठता है कि क्या ठेकेदारों और सरकारी अधिकारियों के बीच मिलीभगत की वजह से ऐसा हो रहा है।

इस वजह से न सिर्फ जनता की मेहनत का पैसा बर्बाद होता है बल्कि लोगों की सुरक्षा को भी खतरा होता है। ऐसे में सरकारों को चाहिए कि निर्माण परियोजनाओं की निगरानी हो और दोषी अफसरों और ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

13 दिन में छह पुल गिरे

बिहार में पिछले 13 दिन में ही छह पुल गिर गए हैं। इससे पहले भी देश भर में कई ऐसी घटनाएं हुई जब उद्घाटन के कुछ ही महीनों या सालों के भीतर निर्माण के ढहने या गिरने की खबर आ गई।

इस तरह की घटनाओं की वजह से सरकारों के कामकाज पर सवाल तो उठे ही, यह भी सवाल उठा कि जनता के टैक्स के पैसे से बने रहे इन पुलों या किसी अन्य निर्माण के गिरने का जिम्मेदार कौन है और आखिर इसकी भरपाई किस तरह की जाएगी। बड़ी संख्या में लोगों ने कहा कि सरकारी महकमों में हो रहा भ्रष्टाचार इसके लिए जिम्मेदार है। कुछ ऐसी घटनाओं को देखते हैं जिनमें उद्घाटन से पहले या उद्घाटन के कुछ सालों के भीतर कहां-कहां इस तरह की घटनाएं हुई हैं।

सबसे ताजा मामला किशनगंज के ठाकुरगंज ब्लॉक का है। यहां पर खोसीडांगी गांव में बन रहा पुल धंस गया और इस वजह से 60 हजार लोगों पर सीधा असर पड़ा है। यह पुल बूंद नदी पर 2009-10 में 35 लाख की लागत से बनाया गया था।

उद्घाटन के तीन महीने बाद ही ढह गई छत

जबलपुर में डुमना एयरपोर्ट के नए विस्तारित टर्मिनल पर 27 जून को भारी बारिश के कारण छत का एक हिस्सा ढह गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन महीने पहले ही इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था।

22 जून को बिहार के सीवान जिले में एक छोटा पुल ढह गया था। इससे पहले पूर्वी चंपारण जिले में 23 जून को एक निमार्णाधीन छोटा पुल भी गिर गया था। 16 मीटर लंबा यह पुल 1.5 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा था। 18 जून को अररिया जिले में पुल ढहने की घटना हुई थी। यह पुल बकरा नदी के पड़रिया घाट पर बन रहा था। पुल के दो पिलर ध्वस्त हो गए थे जबकि एक पाया नदी में धंस गया था। पुल का निर्माण लगभग पूरा हो गया था और इस पर आठ करोड़ रुपये खर्च हो चुके थे।

बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है. बीते मंगलवार को अररिया जिले में 12 करोड़ से बना पुल उद्घाटन से पहले ही धड़ाम हो गया था,अब सीवान में नहर पर बना ब्रिज जमींदोज हो गया है। अभी न तो बारिश हुई है फिर भी पुल धराशायी हो गया.बिहार में एक हफ्ते की अंदर ऐसी तीसरी घटना है।

इसके बाद झारखंड के गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड में अरगा नदी पर बन रहे पुल का गर्डर टूट कर गिर गया जबकि एक और पिलर टेढ़ा हो गया। यह पुल कारीपहरी गांव में 5.5 करोड़ की लागत से बन रहा था। यह पुल मानसून की पहली बारिश को भी नहीं झेल सका।

28 जून की सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर छत का एक हिस्सा गिर गया था। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इस घटना को लेकर विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर हमला बोला था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस घटना की जांच का आदेश दिया था।

तेलंगाना में 49 करोड़ की लागत का पुल गिरा

तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में अप्रैल महीने में एक निर्माणाधीन पुल ढह गया था। इस पुल का शिलान्यास 8 साल पहले हुआ था और इसके निर्माण के लिए 49 करोड़ का बजट रखा गया था। पुल के भुगतान की राशि में देरी होने के कारण इसका निर्माण कार्य रुका था।

22 मार्च 2024 को बिहार के सुपौल में कोसी नदी पर निमार्णाधीन एक और पुल गिर गया था। इस पुल का निर्माण 1200 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा था।

मई, 2023 में बायसी प्रखंड के चंद्रगामा पंचायत में सलीम चौक के पास एक पुल गिर गया था। इस घटना में कई मजदूर घायल भी हुए थे।

जून, 2023 को अगुवानी गंगा घाट पर निमार्णाधीन पुल के पिलर नंबर 10, 11 और 12 नदी में बह गए थे। 19 फरवरी, 2023 को पटना के सरमेरा में फोर लेन पुल गिर गया था।

18 नवंबर, 2022 को बिहार के नालंदा जिले में एक निमार्णाधीन पुल गिर गया था। पुल गिरने से 1 शख्स की मौत हो गई थी। जुलाई, 2022 में बिहार के कटिहार जिले में भी एक निमार्णाधीन पुल गिर गया था और पुल गिरने से 10 मजदूर घायल हो गए थे।

भ्रष्टाचार और निर्माण परियोजनाएं

गुणवत्ता में कमी

भारत में कई बार निर्माण परियोजनाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। हाल के वर्षों में, कई पुल और भवन या तो निर्माण के दौरान गिर गए या उद्घाटन के कुछ समय बाद ही ढह गए। इन घटनाओं ने न केवल सरकार की छवि को धूमिल किया है, बल्कि आम जनता के जीवन और संपत्ति को भी गंभीर खतरे में डाल दिया है।

ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत

निर्माण परियोजनाओं में भ्रष्टाचार का सबसे आम रूप ठेकेदारों और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत है। ठेकेदार गुणवत्ता से समझौता करके परियोजनाओं की लागत को कम करने की कोशिश करते हैं, जबकि सरकारी अधिकारी रिश्वत लेकर इन खामियों को नजरअंदाज कर देते हैं। इस प्रकार, परियोजनाएं समय पर और बजट में तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता बेहद खराब होती है। भ्रष्टाचार के कारण

राजनीतिक दबाव

कई बार राजनीतिक दबाव के कारण निर्माण परियोजनाओं को जल्दबाजी में पूरा करने की कोशिश की जाती है। चुनावों के दौरान सरकारें वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए बड़ी-बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करती हैं, भले ही वे पूरी तरह से तैयार न हों। इस जल्दबाजी में गुणवत्ता और सुरक्षा के मानकों की अनदेखी हो जाती है।

पारदर्शिता की कमी

निर्माण परियोजनाओं में पारदर्शिता की कमी भी भ्रष्टाचार का एक प्रमुख कारण है। टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता न होने के कारण योग्य ठेकेदारों की बजाय रिश्वत देने वाले ठेकेदारों को काम मिल जाता है। इससे परियोजनाओं की गुणवत्ता पर गंभीर असर पड़ता है।

निगरानी की कमी

निर्माण परियोजनाओं की निगरानी में भी भारी कमी है। निर्माण कार्यों की नियमित जांच नहीं होने के कारण ठेकेदार मनमानी करते हैं और गुणवत्ता से समझौता करते हैं। अधिकारी भी इस मामले में लापरवाही बरतते हैं और रिश्वत के लालच में आकर खामियों को नजरअंदाज कर देते हैं।

समाधान और सुधार के उपाय

पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया

निर्माण परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की आवश्यकता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टेंडर केवल योग्य और विश्वसनीय ठेकेदारों को ही मिले। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाना जरूरी है, ताकि कोई भी भ्रष्टाचार न हो सके।

सख्त निगरानी

निर्माण कार्यों की सख्त निगरानी की जानी चाहिए। सरकार को एक स्वतंत्र निगरानी एजेंसी का गठन करना चाहिए, जो नियमित रूप से निर्माण कार्यों की जांच करे और गुणवत्ता सुनिश्चित करे। यदि कोई खामी पाई जाती है, तो ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

समय पर जांच और रखरखाव

निर्माण कार्यों के बाद नियमित रूप से उनकी जांच और रखरखाव किया जाना चाहिए। पुलों और अन्य संरचनाओं की समय-समय पर जांच से उनकी संरचनात्मक स्थिति का पता चलता रहता है और समय रहते मरम्मत की जा सकती है।

योग बनता एकीकृत शक्ति : प्रधानमंत्री मोदी

● **डेस्क**

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में डल झील के किनारे आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में बारिश ने खलल डाला, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर योग करना था। बाद में, उन्हें श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर (एसकेआईसीसी) में योग करते देखा गया। लगातार तीसरी बार पदभार संभालने के बाद से यह उनका जम्मू-कश्मीर का पहला दौरा है। इस वर्ष के उत्सव की थीम, ₹स्वयं और समाज के लिए योग₹ व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सामुदायिक स्वास्थ्य पर योग के प्रभाव पर जोर देती है। श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य जमीनी स्तर पर भागीदारी को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में योग को बढ़ावा देना है। मोदी ने श्रीनगर में डल झील के किनारे स्थित शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर (एसकेआईसीसी) में योग दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। 2014 में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरूआत के बाद से, प्रधानमंत्री ने दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, रांची, लखनऊ, मैसूर और यहां तक कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कर्त्तव्य पथ सहित विभिन्न प्रतिष्ठित स्थलों पर समारोहों का नेतृत्व किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (क्ळ) हर साल 21 जून को मनाया जाता है ताकि समग्र स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए इसके अपार लाभों को उजागर किया जा सके। इस आयोजन की शुरूआत 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी।

पीएम मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को अपने संबोधन के दौरान योग को समर्पित एक वैश्विक दिवस के विचार का प्रस्ताव रखा था। दिसंबर 2014 में, वठ्ळ्ञ ने 21 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया।

संयुक्त राष्ट्र योग को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तत्वों वाली एक प्राचीन प्रथा के रूप में वर्णित करता है, जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। 'योग' शब्द संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ है जुड़ना या एकजुट होना, जो शरीर और चेतना के एकीकरण को दशार्ता है।

2024 योग दिवस समारोह

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सभी से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का आग्रह किया, इसके समग्र लाभों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ₹इस अवसर पर, मैं सभी से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील करना चाहता हूं। योग हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्व को जोड़ता है।₹ - शुक्रवार को 10वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, अनुराग ठाकुर, मनसुख मंडाविया, नितिन गडकरी और अन्य लोगों ने योग किया।

- संस्कृति मंत्रालय शुक्रवार को दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला स्थल पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कुतुब मीनार स्थित सन डायल लॉन में समारोह का नेतृत्व करेंगे।

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को 10वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने इस अवसर पर योग सत्र में हिस्सा लेते हुए कहा, ₹पूरे विश्व समुदाय, खासकर भारत के नागरिकों को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं! योग मानवता को भारत का अनूठा उपहार है। बढ़ती जीवनशैली से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए आज योग कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का मार्ग है। आइए हम योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने का संकल्प लें।₹ - इजरायल में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के भाग के रूप में तेल अवीव में पेरेस सेंटर फॉर पीस एंड इनोवेशन में तीन सौ से अधिक प्रतिभागियों ने योग आसन किए। - सैकड़ों योग उत्साही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए एक कार्यक्रम में एकत्र हुए, जहां अमेरिका में भारत की उप राजदूत श्रीप्रिया रंगनाथन ने एक संबोधन दिया।

पर्यावरण संरक्षण को अपनी आदत बनाए- जस्टिस सुधीर अग्रवाल

● **डेस्क**

पर्यावरण संरक्षण को अपनी आदत में शुमार करें। साल में एक दिन पर्यावरण दिवस मनाने से कुछ नहीं होगा।

नेशनल ग्रीन ट्रायब्यूनल(एनजीटी)के सदस्य जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने यह बातें कहीं।

वे आज आईपी यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इन्वायरॉन्मेंट मैनेजमेंट(यूएसईएम) द्वारा ह्यवर्ल्ड इन्वायरॉन्मेंट डेह्न पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे।

उन्होंने कहा कि प्रदूषण से पूरा समाज प्रभावित होता है। येसे में जागरूकता के साथ समुचित प्रयास की भी जरूरत है।

उन्होंने बताया कि प्राचीन धर्म ग्रंथ ह्यऋग वेदह्न में भी पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख है। थोड़े प्रयास से हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं।

उन्होंने कहा कि एनजीटी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यावरण संरक्षण के बिना विकास अधूरा है।

यूनिवर्सिटी के कुलपति पद्मश्री प्रो. (डॉ.) महेश वर्मा ने इस अवसर पर जानकारी दी कि पानी और प्रदूषण की वजह से ट्रॉपिकल कंट्रीज में ज्यादातर बीमारियाँ हो रही हैं। उन्होंने प्रदूषण कम करने के लिए सामूहिक प्रयास पर बल दिया।

यूएसईएम के डीन प्रो. वरुण जोशी ने इस अवसर पर कहा कि पूरा विश्व किसी न किसी पर्यावरणीय समस्या से आक्रांत है।

जाने- माने पत्रकार राजीव निशाना ने इस अवसर पर पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाने में मीडिया की भूमिका पर बल दिया।

इस अवसर पर यूनिवर्सिटी और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी संस्था ह्य साईकोमह्न के साथ एक एमओएम भी किया गया।

इस अवसर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

कवितावली

सुरेश पुष्पाकर

ग्रेट ब्रिटेन

कभी मैं भी पर्वतों की बुलंदी पर रहकर बादलों को छूता था। कभी मुझे भी मद मस्त पवन के झोंके सहलाया करते थे। मुझमें भी कभी विशालता का अंश होने का एहसास था। मेरी ही बनी कंदराओं ने मानव जाति को सबसे पहले आश्रय दिया।

मुझे, मेरे वजूद से तोड़ा गया। मेरी पहचान पर्वत या चट्टान को मिटाकर पत्थर बनाया गया। यहीं मेरा अन्त नहीं, मुझे अभी और तोड़ा जाना है, मेरे टुकड़े-टुकड़े कर मानव द्वारा चलने के लिए बनाए जाने वाली राहों पर बिछाया जाना है। अपने पाँव तले रौंद कर मुझे मानव कहेगा मैं उसकी प्रगति का हिस्सा बन गया।

एक खदान से निकाले गये कोयले से अपनी व्यथा कहते-कहते पत्थर भावुक हो गया।

कोयले ने अपनी नम आँखों से पत्थर की तरफ देखा और लगभग ढांढ्स बंधाते हुए पत्थर से कहने लगा, तुमसे भी अधिक दुर्गति मेरी होने वाली है। धरती के गर्भ में चैन से मैं सोया हुआ था। मुझे खोद कर निकाला गया। मेरे भी टुकड़े-टुकड़े कर मुझे जलाया जायेगा, मुझसे उपजी ऊर्जा से संचालित होंगे मानव निर्मित उसके विकास में भागीदार कल-पुर्जे। मेरा पूर्णतया अस्तित्व मिटा दिया जायेगा।

शापित है यह मानव मुझ द्वारा कि यह खुद पत्थर दिल हो जायेगा, यह कहते-कहते पत्थर भाव विभोर हो गया। कोयले ने भी पत्थर की बात को स्वीकार्यता देते हुए कहा मेरा वजूद मिटाने वाले मानव को मेरे रंग का असर होगा, इसका मन काला यहाँ तक कि कभी-कभी चेहरा भी मेरे ही रंग से रंगा जायेगा।

फिर पत्थर और कोयला दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते रहे, अपने-अपने अस्तित्व के मिटने के इन्तज़ार में।

प्रो. गुरदीप 'गुल' धीर

चण्डीगढ़, भारत

'गुल' साहिबा की कलम से

तेरी कुरबत से ही जज़्बात पे रानाई है
वरना यह ज़िंदगी एक उम्र की तन्हाई है

एक खला सी है जिधर भी मैं उठाउं नज़रें
जाने किस जुर्म की यह मैंने सज़ा पाई है

चोट खाकर भी देता जो है जीने की दुआ
यह कोई और नहीं आपका सौदाई है

कैसे हो हिजर् के सहरा पै वस्ल की बारिश
कभी क्या काली घटा लेके बाहर आई है

बेरुखी का उन्हें इल्ज़ाम नहीं दे सकते
'गुल' नें तकदीर में लिखी हुई शै पाई है

उदासी के कोहरे से लिपटा है बदन मेरा
मेरे वजूद ने चादर ग़मों की ओढ़ी है

हिजर् की रात लंबी है बहुत लंबी है
ज़िंदगी प्यार की थोड़ी है बहुत थोड़ी है

दूर तक भी नहीं साहिल की कोई परछाई
कैसे मंझधार में कश्ती मेरी, ला छोड़ी है

कुछ टूट गया है फिर भी बंधा है कुछ
किस अदा से तूने रिश्ते की डोर तोड़ी है

कोई हंसी कोई खुशी पहुंचती ही नहीं
संगरेज़ों ने यह दीवार कैसी जोड़ी है

अब अकेले हैं शशोपंज दोराहे का लिए
कौन से मोड़ पै 'गुल' तूने डगर मोड़ी है

कवितावली

मेरी कलम से

डॉ० रामनिवास 'मानव'

नारनौल, हरियाणा, भारत

आज बने इतिहास

मधुर कुंज, छाया घनी, और दृश्य अभिराम ।
मगर समय का 'पाहुना', कब करता विश्राम ॥

छूट गई अमराइयां, हुई छांव भी दूर ।
चलते-चलते आ गए, हम यह कहां हुजूर ॥

दौड़-दौड़कर तन थका, मन भी हुआ उदास ।
बुझे तो कैसे मृग की, मरीचिका से प्यास ॥

धीरे-धीरे सब गया, सुविधा का सामान ।
जीवन बनकर रह गया, जलता हुआ मकान ॥

कंचे, पन्नी, गुड़ियां, हंसी, खुशी, मुस्कान ।
वक्त छीनकर ले गया, कितना कुछ सामान ॥

एक-एक कर सब गए, क्या दुश्मन, क्या मीत ।
अब तो केवल शेष हैं, कुछ यादें, कुछ गीत ॥

कैसा वाद-विवाद अब, कैसा अब परिवाद ।
अब तो जीवन में बचा, है केवल अवसाद ॥

गया, देखते सब गया, हास, लास, उल्लास ।
कल तक हम भूगोल थे, आज बने इतिहास ॥

चाहत के फीके हुए, चटक चटीले रंग ।
इसीलिए लगने लगे, सारे ढंग कुढंग ॥

कोई कहे रखैल है, कोई समझे सौत ।
जीवन की अर्धांगिनी, लगे मुझे तो मौत ॥

सीता-सी संवेदना, व्याकुल और उदास ।
मन बैरागी राम-सा, जीवन है वनवास ॥

कैसा जीवन-राग

कुंठित है सब चेतना, लक्ष्यहीन संधान ।
टेक बने हैं देश की, अब बौने प्रतिमान ॥

नैतिकता नंगी हुई, बनी पाप की टेक ।
लक्ष्मण-रेखा अब यहां, बाकी बची न एक ॥

पूजित है अब नग्नता, धरा शीश पर ताज ।
लेकिन भटके अस्मिता, कौड़ी की मुहताज ॥

नंगा पूछे नंग से, असली नंगा कौन ।
सच दोनों के सामने, फिर भी उत्तर मौन ॥

भुतहा-भुतहा वक्त है, सहमी-सहमी आग ।
सन्नाटों के दौर में, कैसा जीवन-राग ॥

आहत-अपहृत रोशनी, अंधकार की कैद ।
खड़ी घेरकर आंधियां, पहरे पर मुस्तैद ॥

अभयारण्य आज बना, सारा भारत देश ।
संरक्षित शैतान हैं, संकट में दरवेश ॥

राजनीति करने लगी, अब तो स्यापा रोज ।
यार रुदाली के सभी, क्या गंगू, क्या भोज ॥

झूठ करे अठखेलियां, सत्य फिरे लाचार ।
पड़ी धर्म के बेड़ियां, गले पाप के हार ॥

अदरक वाली चाय

अलका कांसरा

चण्डीगढ़, भारत

जब भी पुराना साथी
आता है
पुराने साथियों के बीच
रिटायर हो कर
बिलकुल वैसे ही
जैसे होती है घर वापसी

उम्र के इस पड़ाव पर
बहुत दूर लगते हैं पुराने दिन
न जाने कहाँ गुम हो जाता है
वह बेफ़िक्रापन
वह मासूमियत
बात बात पर हँसना और हँसाना
वह समोसे और पकौड़े खाना
वह नई साड़ी पहन इतराना

जिस दिन मिल बैठता
अपना यह दोस्तों का टोला
लौट आता
वही बचपन
वही बेफ़िक्रापन
फ़ोटो खींचना और खिंचवाना
नई साड़ी पहन इतराना
अदरक वाली चाय पीना पिलाना
समोसे और पकौड़े खाना
वही बात बात पर हँसना और हँसाना
बैठे बैठे खेलते जाना
कच्चा पक्का, पक्का कच्चा
दिल तो है जी अभी बच्चा।

प्याला चाय का

चाय का प्याला
या फिर कोई बहाना
बात आगे बढ़ाने का
एक चाय का प्याला
गपशप और चुटकुलों का रेला
दोस्तों का मेला

रेल का सफ़र हो
या हवाई जहाज़ का
कालेज की कैंटीन हो
या दफ़्तर का कैफ़ेटेरिया
जुड़ जाता
अजनबीयों के बीच भी
जान पहचान का तागा
जब हाथ में हो
चाय का प्याला

मूसलाधार बारिश हो
और सड़क पर
छोटी सी
चाय की दुकान
ठण्डे हाथों में
गर्म चाय का प्याला
कनखीयों से देखना
और शुरू
प्यार का सिलसिला
बात फ़िल्मी ही सही
पर ग़लत नहीं

सुस्ताई सी
अलसाई सी सुबह
गुलाबी सा मौसम
हाथ में जादुई प्याला
हमसफ़र का साथ
निकलती गई
बात में से बात
चाय समाप्त
पर बात तो अभी बाक़ी है
एक प्याला और सही

17 साल बाद हरियाया सुनहरा सपना

तरूण कुमार निमेष

17 साल के लंबे सूखे के बाद आखिरकार भारतीय क्रिकेट के विश्व विजेता बनने के सपने सच हो गए हैं। 29 जून को बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका की टीम के खिलाफ टी -20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में जब भारतीय टीम खेलने के लिए उतरी, तब से ही भारतीय खिलाड़ियों एवं समर्थकों के हौसले सातवें आसमान पर थे ।

पिछले विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में हारने के बाद एक कसक मन में रह गई थी । उस प्रतियोगिता में भी भारतीय टीम फाइनल से पहले तक अविजित रही थी और अपने पूल मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पराजित भी किया था लेकिन आखिरी समय पर कंगारूओं की पकड़ से वह कप निकालने में चूक गए थे । उस मैच की कई समानताएं इस मैच में भी रहीं । उस टूर्नामेंट में भी रोहित धमाकेदार शुरूआत कर रहे थे, गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे पर फाइनल में नहीं चल पाए थे इस बार भी ऐसा ही हुआ । तब भी पहले भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की थी और इस बार भी भी बल्लेबाजी चुनी। 'चोकर' कहे जाने वाला अफ्रीका भी पिछले लंबे समय से फाइनल एवं सेमीफाइनल में जाकर हारता रहा है तो इस बात की भी आशंकाएं मन में थी कि कहीं कई हारों के बाद विजय की कहानी अफ्रीका न लिख दे लेकिन जिस तरह पहले ही ओवर में 15 रन बनाए गए, उस से लगा कि इस बार बहुत बड़े संकल्प के साथ यह टीम उतरी है लेकिन जल्दी ही उतावलेपन से स्कोर हो गया 6 ओवर में तीन विकेट पर 34 रन और यह चिंताजनक स्थिति थी।

विराट पिछले मैचों में असफल रहे थे और चारों तरफ उनकी तथा उन्हें निरंतर खिलाने की आलोचना हो रही थी लेकिन इस बार जिस विराट के दर्शन हुए, वह विराट पुराना ही विराट था और उसने बेहतरीन जिम्मेदारी भरी पारी खेली । फाइनल में विराट का साथ मुख्य रूप से अक्षर पटेल और बाद में हार्दिक पांड्या ने अच्छे रन बनाकर दिया तो स्कोर बोर्ड पर 176 का सम्मानजनक स्कोर दिखाई दिया ।

इस टूनामेंट में अधिकतर मैच कम स्कोर वाले रहे हैं लेकिन यह फाइनल मैच था और पूरी संभावना थी कि अफ्रीका चीते किसी दृढ़ता और फुर्ती के साथ टूट पड़ेंगे पर उन्होंने संभल कर शुरूआत की लेकिन जल्दी ही जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप, कुलदीप और हार्दिक पांड्या ने अफ्रीका को बैक फुट पर धकेल दिया। पर अभी तो क्रिकेट का असली रूप देखा जाना बाकी था इसके बाद जिस तरह कार्लसन और डेविड मिलर ने गति पकड़ी ,उसने भारतीय प्रसंशको के दिलों की धड़कनें रोक दी । एक समय वें चार विकेट पर 151 पर खेल रहे थे और प्रति ओवर केवल 6 रन की आवश्यकता थी तब लग रहा था कि अब भारतीय इस प्रतियोगिता में विजेता नहीं बन पाएंगे ।

ऐसे संकट काल में जसप्रीत बुमराह को वापस लाया गया और उन्होंने अपने ऊपर दिखाए गए विश्वास को विकेट चटकाकर सही सिद्ध किया । अर्शदीप और हार्दिक पांड्या ने भी जबरदस्त गेंदबाजी की । इससे पहले अक्षर पटेल के एक ओवर में 24 रन आने से अफ्रीका ने मैच पर जबरदस्त पकड़ बना ली थी और मैच भारत की पकड़ से लगभग निकल चुका था।

कभी इधर तो कभी उधर झूलते इस रोमांचक मैच ने खिलाड़ियों की ही नहीं, दर्शकों की भी धड़कनें बढ़ाकर रखी लेकिन जिस तरह बल्लेबाजी में असफल रहे सूर्यकुमार यादव ने डेविड मिलर का कैच अद्भुत और चमत्कारिक ढंग से लपका. उसने 1983 में कपिल देव द्वारा पकड़े गए विवियन रिचर्ड्स के कैच की याद ताजा कर दी । सोचिए यदि हार्दिक पांड्या की वह गेंद छक्के के

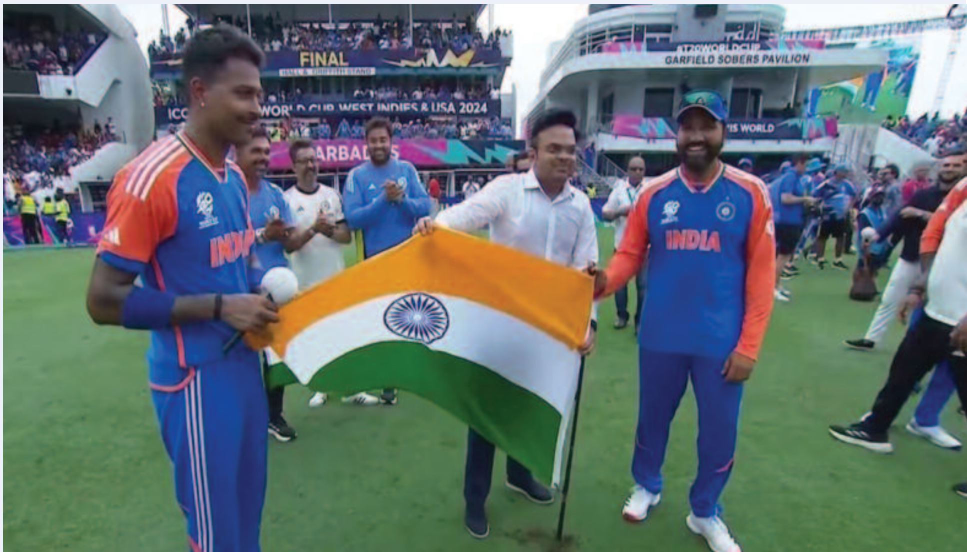

लिए सीमा रेखा के पार चली जाती तो क्या होता ? पर यही तो क्रिकेट है ऐसा नहीं हुआ और बाउंड्री के बाहर हवा में जाती हुई गेंद को किसी हवाई गोताखोर की तरह सूर्यकुमार यादव अंदर लाकर कैच पकड़ने में कामयाब हुए । इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने अफ्रीकियों को सांस नहीं लेने दी ।

यदि जसप्रीत बुमराह को क्रिकेट के इस इंस्टेंट फॉर्मेट का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज कहा जाए तो कतई गलत नहीं होगा पूरे टूनार्मेंट में उन्होंने बल्लेबाजों को रनों के लिए तरसा दिया आखिरी ओवर में 16 रन का लक्ष्य कतई आसान नहीं था हार्दिक पांड्या ने अपनी भूमिका बेहतरीन तरीके सेअपने टीम के साथियों के साथ निभाई और इसी का परिणाम था कि आईसीसी टी-20 कप की चमचमाती ट्रॉफी को टीम इंडिया की तरफ से हिटमैन रोहित शर्मा चूम रहे थे। पर यदि कहा जाए कि जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह के हार्दिक पांड्या से पहले फेंके गए दो ओवरों ने अफ्रीका को शिकंजे में जकड़ा और भारत को विश्व कप दिलवाया तो यह गलत नहीं होगा। भारत के हिस्से में यह तीसरा विश्व कप आया है। इससे पूर्व कपिल देव एवं महेंद्र सिंह धोनी भारत को यह गौरव दिलवा चुके थे ।2007 में जीते गए विश्व कप के बाद सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट से विदाई ले ली थी और इस बार एक साथ दो महारथियों रोहित शर्मा एवं विराट कोहली ने टी- 20 क्रिकेट को अलविदा कहने का संकल्प लिया है ।यह इन दोनों खिलाड़ियों का बड़प्पन है कि उन्होंने अपने आप नए खिलाड़ियों के लिए जगह बनाने का जज्बा दिखाया है । हालांकि भारतीय क्रिकेट उन्हें बहुत मिस करेगा लेकिन उनके इस जज्बे को सलाम भी किया जाएगा ।

राहुल द्रविड़ ने जिस तरह एक संरक्षक व उत्प्रेरक के रूप में कोच की भूमिका निभाई उसने उनसे पूर्व भारतीय टीम के कोच रहे जॉन राइट को भुला दिया है। उम्मीद है आगे भी भारतीय टीम को कोई ऐसा कोच मिले कि द्रविड़ की याद न आए हालांकि एक खिलाड़ी एवं कोच के रूप में राहुल द्रविड़ को भूलना आसान नहीं होगा।

सफलता एक ऐसा अमृत होता है जो आपको चिरायु करता है अमर बनाता है और आपकी स्मृतियों को लंबे समय तक लोगों के दिलों दिमाग में रखता है ।लेकिन इसमें एक नशा भी होता है और कई बार सफलता के शिखर पर पहुंचकर शिथिलता, अहंकार एवं अति आत्मविश्वास भी आ जाता है जो आगे जाकर पतन का कारण बनता है ।इस भारतीय टीम में अब अधिकांश खिलाड़ी बहुत युवा हैं उन्हें मिले खुद को भी संयत रखते हुए आगे बढ़ते रहना होगा तभी भारतीय क्रिकेट शिखर पर बना रह पाएगा।

खैर सफलता के इस जश्न के वक्त कमियां ढूंढना या आलोचना करना अथवा उपदेश देना शमी समीचीन नहीं है ।अभी तो सफलता का जश्न है. इसका आनंद लिया जाना चाहिए ।पूरा देश झूम रहा है, खिलाड़ी झूम रहे हैं और क्रिकेट भी झूम रहा है इससे दूसरे खेल और उसके खिलाड़ियों तथा प्रशासकों को भी प्रेरणा और सीख लेनी चाहिए । ईश्वर करें भारत रूपी सूर्य केवल क्रिकेट में ही नहीं अभी तो दूसरे खेलों के साथ-साथ हर क्षेत्र में अर्शदीप बनकर चमकता रहे। भारतीय आकाश का यह 'रोहित' अपने 'विराट' 'जस' को 'हार्दिक' रूप से 'अक्षर अक्षर' जीवंत रखकर सदैव चमकता रहे यही कामनाएं हैं।

बॉलीवुड के अनकहे किस्से

जब तांगा था प्राण के पास

● **डेस्क**

प्रख्यात खलनायक एवं चरित्र अभिनेता प्राण एक आम भारतीय की तरह हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल खेलने और देखने के तो शौकीन थे ही उनकी अन्य कई रुचियां भी थीं। उनके शौक इतने विविधतापूर्ण थे और एक-दूसरे से ऐसे घुले-मिले थे कि उन सबके मेल से उन जैसे अनोखे व्यक्तित्व का निर्माण होना लाज़िमी था। वह फुर्सत होने पर बागवानी करते, किताबें पढ़ते। कहीं बाहर शूटिंग के लिए जाते तो पाइप और छड़ियां इकट्ठी करते। जानवरों और अच्छी गाड़ियों से भी उन्हें बेहद प्यार था। प्राण और उनकी पत्नी दोनों को ही कुत्तों से बेहद प्यार था। शादी के बाद उनकी पत्नी जब दिल्ली से लाहौर गईं तो उनके ताऊजी की बेटी ने उन्हें एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता उपहार में दिया था ताकि प्राण के काम पर चले जाने के बाद उन्हें घर में अकेलापन न लगे।

विभाजन के चलते यह कुत्ता उन्हें लाहौर छोड़ना पड़ा जिसका दुख उन दोनों को आजीवन रहा। वह कहते थे विभाजन में मुझसे छीनने वाली सबसे मूल्यवान चीजों में से एक मेरे कुत्ते थे। फिर जब से बम्बई में उनका अपना घर हुआ उनके परिवार में हमेशा कुत्ते रहे। बांद्रा में कई अल्सेशियन के साथ उनके पास बोंजो नामक एक गोल्डन रेट्रिवर तथा एक जेट ब्लैक कोकर स्पेनियल तथा सफेद पामेरेनियन भी था जिन्हें वह व्हिस्की और सोडा कहते थे। कुछ समय उनके पास सिल्की

प्राण को बागवानी का भी शौक था। उन्हें गुलाब का फूल बेहद पसंद था जिसकी अच्छी किस्म लाने के लिए वह पुणे की नर्सरी तक जाते थे। उन्हें कैक्टस का भी शौक था। उनके बगीचे में तीन से चार सौ तरह के कैक्टस थे, 10 - 12 फीट ऊंचे से लेकर दो-तीन इंच छोटे तक। फलों के पेड़ों में चीकू, नींबू ,आम, नारियल, शरीफा तो उनके बगीचे में थे ही वह गन्ना भी उपजाते थे। प्राण को गाड़ियों का बहुत शौक रहा।

सिडनी का जोड़ा था जिसे उन्होंने लैला-मजनूं का नाम दिया था। शूटिंग से लौटने पर यह सारे कुत्ते भौंककर उनका स्वागत किया करते थे। इन सात कुत्तों के लिए उन्होंने अपने घर में एक विशेष कैनल का भी निर्माण कराया था। इतना ही नहीं कई बार वे शूटिंग से भी कई जानवर जैसे तोता, हिरण और बंदर भी घर ले आए। कुछ समय उन्होंने रेस के लिए घोड़े भी पाले।

प्राण को बागवानी का भी शौक था। उन्हें गुलाब का फूल बेहद पसंद था जिसकी अच्छी किस्म लाने के लिए वह पुणे की नर्सरी तक जाते थे। उन्हें कैक्टस का भी शौक था। उनके बगीचे में तीन से चार सौ तरह के कैक्टस थे, 10 - 12 फीट ऊंचे से लेकर दो-तीन इंच छोटे तक। फलों के पेड़ों में चीकू, नींबू ,आम, नारियल, शरीफा तो उनके बगीचे में थे ही वह गन्ना भी उपजाते थे। प्राण को गाड़ियों का बहुत शौक रहा। फिल्मों में काम शुरू करने से पहले लाहौर में उनके पास एक साईकिल और एक तांगा था जिसका जिक्र उर्दू के मशहूर लेखक सआदत हसन मंटो ने कुछ इस तरह किया है, प्राण काफी सुंदर थे और अपने सलीकेदार फैशनेबल कपड़ों तथा शानदार तांगे के लिए लाहौर में काफी लोकप्रिय थे। उन दिनों वे शाम को तांगे पर सैर किया करते थे। फि ल्मों में काम शुरू करने के बाद उन्होंने लाहौर में एक मोटर साईकिल भी खरीदी जिसके एक्सीडेंट केस में फंसने पर 25 रुपए का जुमार्ना भी हुआ था जिसे मजिस्ट्रेट ने उनकी सुंदर आँखें देखकर 5 रुपए कर दिया था। बम्बई में उनके द्वारा खरीदी गई पहली गाड़ी हिलमैन थी जो उन्होंने 1951 में बहार फिल्म के प्रीमियर से कुछ दिन पहले ही खरीदी थी। उसके बाद उन्होंने 'क्रिस्टल', एम.जी. रोडस्टर और 'शेवरलेट' भी ली। उनके पास 1930 से पहले बनी दो आस्टिन विंटेज कारें भी थीं।

प्राण के पास पाइप का भी विपुल संग्रह था। धूम्रपान छोड़ने पर उन्होंने उन्हें अपने यार-दोस्तों को बांट दिया। उनके पास छड़ियों का भी विशाल संग्रह था। वे जब भी कहीं जाते वहां से अलग-अलग तरह की छड़ियाँ लाने की कोशिश करते।

प्राण का उर्दू शायरी का ज्ञान और उनके शेर पढ़ने की कला भी जगजाहिर थी और इसके चलते वे अपने सह कलाकारों में बेहद लोकप्रिय भी थे। मनोज कुमार ने एक बार बताया था कि प्राण साहब को अनगिनत शेर याद थे। उन्हें असगर गोंडवी, फैज फैज अहमद फैज, फिराक गोरखपुरी और जोश मलीहाबादी जैसे शायरों के कलाम मुँह जुबानी याद थे। प्राण के पास पुस्तकों का भी बेहतरीन संग्रह था और उनकी रुचि भी विस्तृत थी। अनेक उपन्यासों से लेकर अनेक शास्त्रीय ग्रंथ भी उनके संग्रह में थे। अरेबियन नाइटस और द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के सभी कीमती भाग भी उनके पास थे।

प्राण साहब शराब के भी बेहद शौकीन थे। शूटिंग से घर आने के बाद नहा-धोकर वे नियमित रूप से शराब पीया करते थे। इसलिए उनके पास सैंकड़ों तरह के गिलासों के साथ ही बियर मगों का भी मंहगा और बड़ा संग्रह था। खेलों में हॉकी के लिए दीवानापन छात्र अवस्था से ही था। अपने स्कूल में वह हॉकी खेलते थे। बॉम्बे प्रोविंशियल हॉकी एसोसिएशन के वे सक्रिय सदस्य थे। बेबोर्न स्टेडियम में होने वाले हर बडे क्रिकेट मैच को देखने के लिए वे बॉम्बे क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के सदस्य बन गए थे। यानी बॉम्बे में होने वाले हर महत्वपूर्ण फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट मैच को देखते थे। फुटबॉल का शौक उन्हें नरगिस के बड़े भाई अख्तर हुसैन ने लगाया था। 50 के दशक में प्राण ने राज कपूर के साथ मिलकर एक क्लब भी बनाया जिसका नाम था बॉम्बे डायनामोज फुटबॉल क्लब। इसमें उन्होंने कई भारतीय ओलंपिक खिलाड़ी शामिल किए थे। उन्होंने कई चैंपियनशिप भी जीती। खेलों में शामिल होकर वे अपनी थकान दूर कर तारोताजा हो जाते थे। बाद में कई क्रिकेट फुटबॉल के चैरिटेबल मैच खेलकर प्राण ने परोपकार व जन सेवा के लिए खूब धन भी जुटाया।

चलते-चलते

प्राण के अपने समकालीन नायकों से बेहद अच्छे रिश्ते रहे। उन्होंने दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद की तिकड़ी से लेकर बाद के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन तक सभी के साथ काम किया। राज कपूर के साथ उनके रिश्ते पाकिस्तान की पृष्ठभूमि होने के कारण विशेष थे। अपनी चौथी ही फिल्म आह (1953) में राज कपूर ने उन्हें एक भले डॉक्टर की भूमिका के लिए चुना जबकि वह उसे समय एक कामयाब चर्चित और लोकप्रिय खलनायक हो चुके थे। उसके बाद में वे उनकी हर फिल्म का हिस्सा रहे। बॉबी फिल्म तक। बॉबी के निर्माण के समय उनकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। वह मेरा नाम जोकर की असफलता के कारण कर्ज में डूबे हुए थे। राज कपूर जब उन्हें बॉबी फिल्म के लिए साइन करने गए तो संकोच के साथ कहा, मैं इस वक्त आपको कुछ भी नहीं दे सकूंगा। प्राण ने उनसे पूछा क्या आपकी जेब में एक रुपए का सिक्का है? राज कपूर कुछ चकराए तब प्राण ने अपना पूरा वाक्य किया- मेरी फीस बस इतनी ही होगी।

फिल्म कल्कि में तड़के का काम कर रही दिशापाटनी

फिल्म कल्कि 2898 में दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और कमल हासन जैसे स्टार्स अपना दमखम दिखा रहे हैं। फिल्म के डायरेक्शन की कमान नाग अश्विन ने संभाली है। नाग अश्विन ने एक वीडियो में बताया था कि उन्होंने कल्कि के संसार की रचना ये ध्यान में रखते हुए की है कि जब दुनिया खत्म होने वाली होगी तो ये संसार कैसा नजर आएगा। फिल्म ने आज यानी 27 जून को सिनेमाघरों में दस्तक दी है। फिल्म कोई भी हो अमिताभ बच्चन की एंट्री होते ही दर्शकों का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है। कल्कि के साथ भी ऐसा ही हुआ,अमिताभ की एंट्री होते ही थिएटर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पर्दे पर फिल्म के पहले सीन से ही लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से सिनेमाघर गूंज उठा था।

फिल्म की शुरूआत में अमिताभ का यंग अवतार नजर आया। फिल्म में बिग बी का लुक देख फैंस एक बार फिर से उनके मुरीद हो गए है। फिल्म की शुरूआती कहानी आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है। लेकिन फिल्म के एक्शन सींस हैरान करने वाले हैं। पहले कभी आपने किसी बॉलीवुड फिल्म में ऐसे एक्शन सीन नहीं देखे होंगे। ये फिल्म देखते समय आपको हॉलीवुड फिल्म की तरह ही अहसास होगा। ये थोड़ी अलग टाइप की फिल्म है। फिल्म में प्रभास (भैरवा) की एंट्री काफी धमाकेदार दिखाई गई है। पर्दे पर उनकी फर्स्ट अपीयरेंस पर दर्शकों ने खूब तालियां बजाई और सिटी बजाकर अपने चहीते स्टार को चेयरअप किया। पर्दे पर प्रभास की एंट्री होते ही फैंस की एक्साइटमेंट का लेवल देख ये बात तो साफ हो जाती है कि प्रभास के आते ही फिल्म का इंट्रेस्ट लेवल कई गुणा बढ़ गया है। फिल्म में दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी की एंट्री तो तड़के काम कर रही हैं। फिल्म में दोनों ब्यूटी क्वीन की एंट्री होते ही फिल्म में नया मोड़ आया है। दोनों ही अपने ग्लैमर अवतार से फैंस का दिल जीत रही हैं।

A Venture of
vedika
Designers'
Ladies Boutique
Customize tarling
vedika
FASHION
international
A UNIT OF
5N
MART
Doorstep Services
Call: +91 76695 63666

now open

ROCKING WOODS

a musical restaurant

• INDIAN • CHINESE • CONTINENTAL

25%* CORPORATE & STUDENT DISCOUNT

* UPTO 7:30PM
conditions apply

At Rocking Woods we have combined the two most relaxing elements, music & nature.
Surrounded in a wooden feel, you will feel the music reverberating through your body. The drinks & foods will just add some more soul making this one of your favorite hangouts.

Fun Cinema Bldg., V3S Mall, Delhi-92